



82

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

लेखक.....

शीर्षक.....

[illegible]

८४
८९

18047

गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान
आदि न लगायें।

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

४४

वर्ग संख्या ४५

आगत संख्या 18047

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

GOL", JULY, 1938 ADHUNIK ITIHAS ATLAS No.

“भूगोल”

आधुनिक इतिहास-एटलस

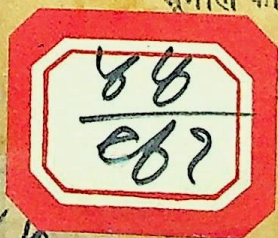
सम्पादक

रामनारायण मिश्र, बी० ए०



प्रकाशक

भूगोल-कार्यालय, प्रयाग



ANNUAL
SUBSCRIPTION

Indian: Rs. 3/-

Foreign: Rs. 5/-

This copy: As. 8

* ओ३म् *

पुस्तक-संख्यां ८८/८९

पंजिका-संख्या ... १-८०८६

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई महाशय १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

भूगोल-एटलस

११२ पृष्ठ, ३०० से ऊपर रङ्गीन
और सादे नक्शे

संयुक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त तथै वरार के शिक्षा-विभाग
द्वारा स्कूलों के लिये स्वीकृत

मूल्य १।)

प्रकाशक—भूगोल-कार्यालय, इलाहाबाद

४४
४९

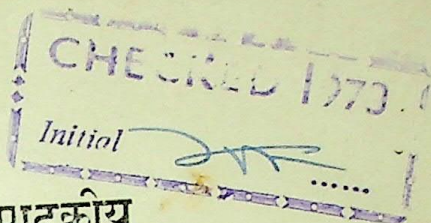
२२.४६
२५.६.०५

पुस्तकालय

उरुकुल कांगड़ी

विक्रम संमतीकरण १९५४-१९५५

ग
क
क
व
प
मि
व
ड
ए
ः
ः



सम्पादकीय

आधुनिक इतिहास-एटलस अंक की योजना बहुत पहले की गई थी। बड़ी तेजी के साथ बदलने वाले देशों की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये हिन्दी में एक भी पुस्तक न थी। दूसरे देशों की राजमर्रा की जटिल समस्याओं का समझना अपने देश-वासियों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये “भूगोल” के पन्द्रहवें वर्ष के उपलक्ष में यह विशेषांक पाठकों की सेवा में भेंट किया जाता है। दैनिक अखबार पढ़ने वालों और संसार की घटनाओं से रुचि रखने वालों को प्रायः प्रति दिन आधुनिक इतिहास-एटलस की आवश्यकता होगी। इसीलिये इस अंक को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक नक़शे के सामने उसका विवरण है। पहले “भूगोल” का गंगाङ्क इसी जुलाई में और यह अंक आगामी जनवरी, १९३९ में प्रकाशित करने का विचार था। पर कुछ आकास्मिक कारणों से गंगा अंक तयार न हो सका। अतः क्रम बदलना पड़ा। अब गंगाङ्क आगामी (१९३९) जनवरी में पाठकों की सेवा में भेजा जायगा।

प्रस्तुत अंक बड़ी जल्दी में निकालना पड़ा। इससे तीन नक़शे (पेलेस्टाइन, ईरान-वरमा-स्याम) पुराने देने पड़े। एक दो और त्रुटियाँ रह गईं। फिर भी यदि पाठकों ने इसे पसन्द किया तो प्रतिवर्ष इसकी नई आवृत्ति निकाली जा सकेगी। इससे प्रतिवर्ष देशों के प्रधान परिवर्तनों को पाठक एक सामयिक एटलस की सहायता से समझ सकेंगे।

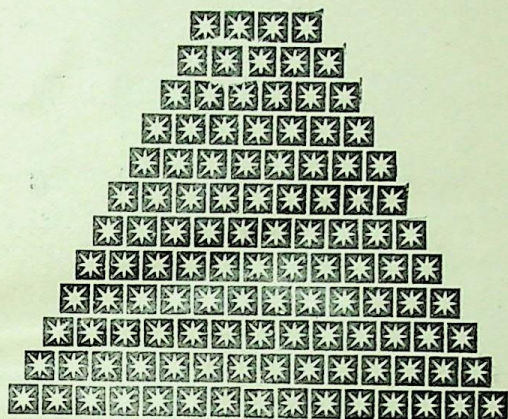
इस अंक की तयारी में महाशय होराविन की करेन्ट हिस्टरी एटलस और वोमैन को न्यूवर्ल्ड आफ टुडे से बड़ी सहायता मिली। हम दोनों ही सज्जनों के ऋणी हैं।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१ वर्सेल्स की सन्धि	२-३
२ जर्मनी की पश्चिमी सीमा	४-५
३ जर्मनी के पड़ोसी	६-७
४ जर्मनी की पूर्वी सीमा	८-९
५ बड़ी लड़ाई में रूस के खोये हुए प्रदेश	१०-११
६ बाल्टिक तट की रियासतें	१२-१३
७ पोलैंड की पूर्वी सीमा	१४-१५
८ यूक्रेन	१६-१७
९ लड़ाई से आस्ट्रिया-हंगारी की हानि	१८-१९
१० आस्ट्रिया	२०-२१
११ लिटिल एण्टेण्ट (लघु मित्रदल)	२२-२३
१२ हंगारी	२४-२५
१३ इटली यूगोस्लैविया और एड्रियाटिक	२६-२७
१४ लिटिल एण्टेण्ट—(१) यूगोस्लैविया	२८-२९
१५ यूगोस्लैविया की जातियाँ	३०-३१
१६ चेकोस्लोवेकिया	३२-३३
१७ रूमानिया	३४-३५
१८ बल्गेरिया	३६-३७
१९ ग्रीस (यूनान)	३८-३९
२० पूर्वी और मध्य योरोप के अल्पसंख्यक लोग	४०-४१
२१ योरोप के नवीन राष्ट्र	४२-४३
२२ योरोप के भीतरी राज्य	४४-४५
२३ आयरलैंड	४६-४७

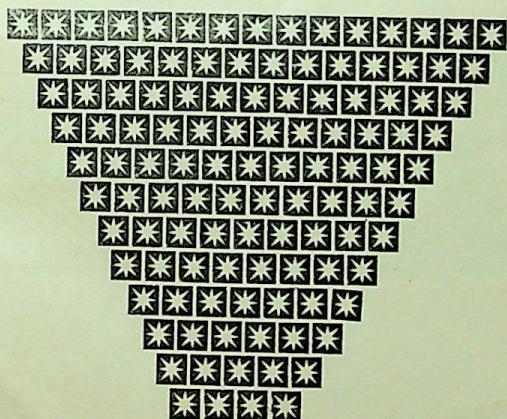
विषय	पृष्ठ
२४ स्पेन की गृह-कलह	४८-४९
२५ ब्रिजियम की जातियाँ	५०-५१
२६ भूमध्य सागर में जातियों का संघर्ष	५२-५३
२७ बड़ी लड़ाई से टर्की का हास	५४-५५
२८ टर्की	५६-५७
२९ पूर्वी प्रदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य	५८-५९
३० फ्रांस और पश्चिमी भूमध्य सागर	६०-६१
३१ इटली और लालसागर	६२-६३
३२ एशियाई	६४-६५
३३ इन्डो-सऊदी की विजय	६६-६७
३४ इराक का तेल और मार्ग	६८-६९
३५ पेलोस्टाइन में यहुदियों के उपनिवेश	७०-७१
३६ ईरान का तेल और रेलवे	७२-७३
३७ पूर्वी एशिया में शक्तियों का जमघट	७४-७५
३८ जापानी साम्राज्य	७६-७७
३९ चीन में घुसने के मार्ग	७८-७९
४० मंगोल लोगों का देश	८०-८१
४१ मंचूक्यो और रूस-जापान	८२-८३
४२ चीन विच्छेद	८४-८५
४३ नानकिंग की सरकार	८६-८७
४४ नवीन रूस	८८-८९
४५ नवीन रूस के राजनैतिक विभाग	९०-९१
४६ योरोपीय रूस के राजनैतिक विभाग	९२-९३
४७ काकेशस	९४-९५
४८ पश्चिमी साइबेरिया और तुर्किस्तान	९६-९७
४९ मध्य एशिया की जातियाँ	९८-९९

विषय	पृष्ठ
५० मध्य एशिया की सीमायें और अफ़ग़ानिस्तान	... १००-१०१
५१ रूस का सबसे अधिक पूर्वी प्रदेश	... १०२-१०३
५२ सुदूर पूर्वी देशों का चौराहा	... १०४-१०५
५३ ब्रिटिश मलय	... १०६-१०७
५४ भारतवर्ष-कांग्रेसी प्रान्त	... १०८-१०९
५५ बरमा और स्याम	... ११०-१११
५६ तिब्बत	... ११२-११३
५७ अफ़्रीका के स्वाधीन राज्य	... ११४-११५
५८ अफ़्रीका में जर्मनी के खोये हुए प्रदेश	... ११६-११७
५९ अफ़्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य	... ११८-११९
६० रोडेशिया	... १२०-१२१
६१ दक्षिणी अफ़्रीका के संरक्षित राज्य	... १२२-१२३
६२ ब्रिटिश ईस्ट अफ़्रीका	... १२४-१२५
६३ लाइवेरिया	... १२६-१२७
६४ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हथियों की समस्या	... १२८-१२९
६५ संयुक्तराष्ट्र अमरीका और के रीबियन सागर	... १३०-१३१
६६ क्यूबा	... १३२-१३३
६७ पनामा और निकारेगुआ	... १३४-१३५
६८ प्रशान्त महासागर में राष्ट्रों का संघर्ष	... १३६-१३७
६९ दक्षिणी अमरीका में संयुक्त राष्ट्र का साम्राज्यवाद	... १३८-१३९
७० बोलिविया और पेरू की लड़ाई	... १४०-१४१
७१ बोलिविया	... १४२-१४३
७२ दक्षिणी अमरीका की जातियाँ	... १४४-१४५
७३ न्यूफ़ाउंडलैंड	... १४६-१४७



आधुनिक इतिहास

एटलस

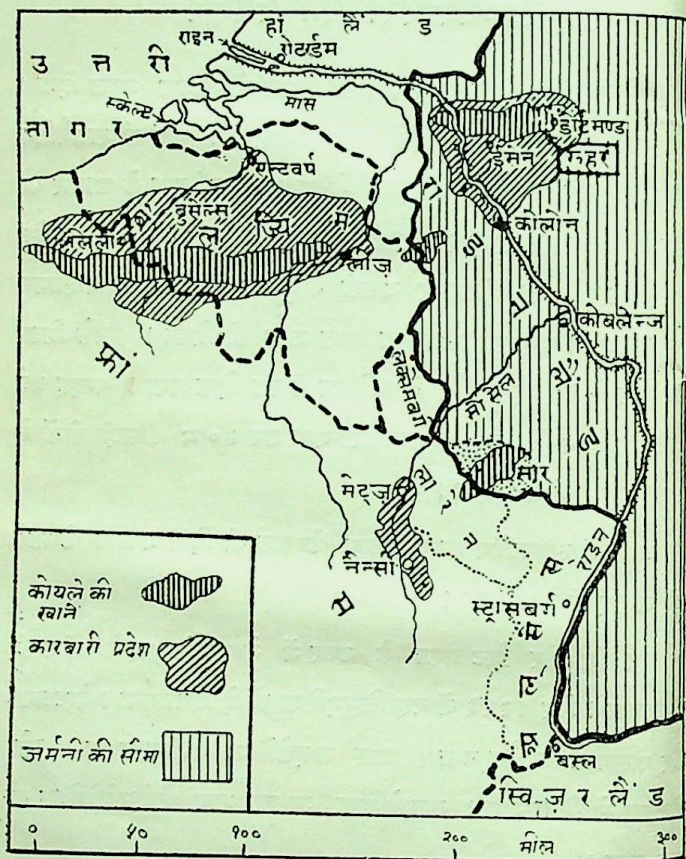


१-वर्सेल्स की सन्धि

बड़ी लड़ाई ने योरूप के राजनैतिक नक्शे को एकदम बदल दिया । इतने भारी परिवर्तन यहां सदियों से नहीं हुए थे । यहां की राजनैतिक सीमायें राष्ट्रपति विल्सन के सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रीयता के आधार पर की गई थीं । पर इनसे योरूप को गहरा आर्थिक धक्का पहुंचा । इस सन्धि के अनुसार पश्चिमी सीमा पर जर्मनी ने यूपेन और मल्मेडी बेल्जियम को सौंप दिये । अल्सेस लारेन का प्रान्त फ्रांस को मिला । इससे मिला हुआ सार बेसिन पहले लीग के अधिकार में रख दिया गया । पन्द्रह वर्ष के बाद १९३५ में जब लोकमत लिया गया तब ६०% फीसदी लोगों ने जर्मनी के पक्ष में मत दिया ।

उत्तर में स्केल्जविग का कुछ भाग डेन्मार्क को दिया गया । डेन्मार्क बड़ी लड़ाई में तटस्थ रहा ।

पूर्व की ओर ईस्ट प्रशा के उत्तर में मेमललैंड पहले लीग को सौंपा गया । फिर १९२३ में यह लिथुएनिया को दे दिया गया । वेस्ट प्रशा और पोसन से पोलैंड बना । अपर साइलेशिया के भाग्य का निर्णय लोकमत से किया गया । साइलेशिया का कुछ भाग चेकोस्लोवेकिया को मिल गया ।



२-जर्मनी की पश्चिमी सीमायें

उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, रूहर, सार और लॉरेन के कोयले और लोहे के प्रदेश में राइन और उसकी सहायक मोसेल नदी और म्यूज़ और स्केल्ट नदियां प्राकृतिक जलमार्ग बनाती हैं। यहाँ पर कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है। राजनैतिक सीमायें लगातार सदियों से बदलती रही हैं। बाल शहर से लेकर स्ट्रासबर्ग से कुछ आगे तक राइन नदी लगभग १०० मील तक (बायें किनारे पर) फ्रांसीसी नदी हो जाती है। इसके आगे ३०० मील तक वह जर्मन नदी बन जाती है। लेकिन राइन का मुहाना हालैंड में है। राष्ट्रीय सीमाओं को अलग करके यदि इस ओर आर्थिक सीमायें निर्धारित की जावें तो इधर के झगड़े सुलभ सकते हैं।

वर्सेलस सन्धि के अनुसार फ्रांस और बेल्जियम की सीमा के पास वाले राइनलैंड में सेना रखने की मनाई कर दी गई थी। लेकिन १९३६ ई० में जर्मन फौजें यहां आकर डट गईं।

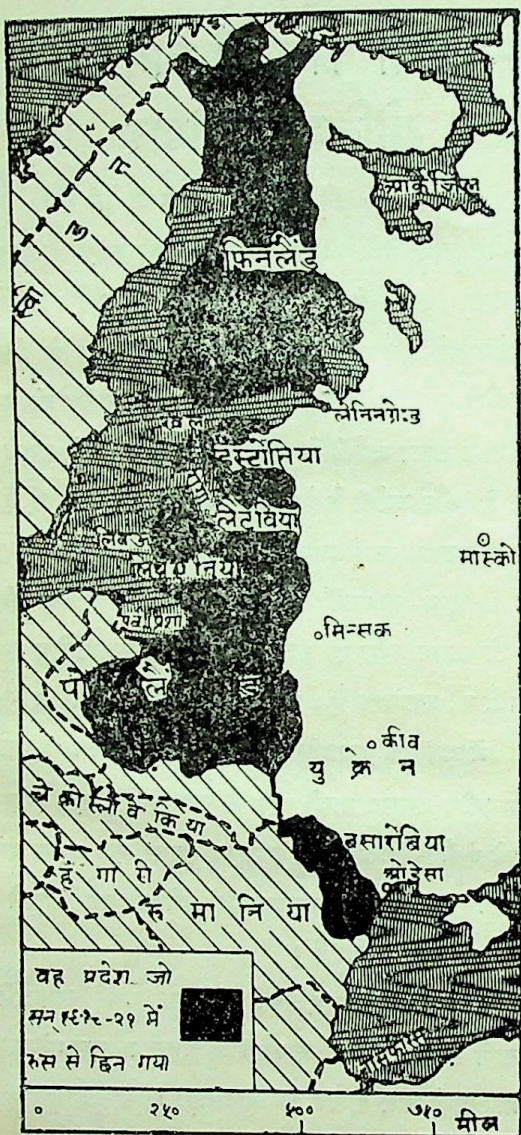
३-जर्मनी के पड़ोसी

फादरलैंड (पितृभूमि) के झंडे के नीचे मध्य योरोप के सब जर्मन लोगों को इकट्ठा करना जर्मन नाज़ी लोगों का प्रधान उद्देश्य है । हर हिटलर की इस घोषणा से जर्मनी के कमज़ोर पड़ोसी डरने लगे हैं । अल्प संख्या में कुछ जर्मन लोग हालैंड स्विज़रलैंड, चेकोस्लोवेकिया, हंगारी, रूमानिया, पोलैंड और लिथुएनिया में रहते हैं । इनके अतिरिक्त आस्ट्रिया एक जर्मन राष्ट्र हो गया है । केवल वहां के जर्मन अधिकतर रोमन कैथोलिक हैं । इस समय जर्मनी की विदेशी नीति पश्चिमी सीमा को न छेड़ने की है । लेकिन डेन्ज़िग, मेमेल और पोलिश कारीडार को जर्मन लोग यथाशीघ्र सुधारना चाहते हैं । नाज़ी नेता रूस से यूक्रेन को भी अलग करना चाहते हैं । इस प्रदेश को वे पोलिश कारीडार के बदले में पोलैंड को देना चाहते हैं अथवा वहाँ जर्मनी द्वारा संरक्षित स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं है ।

४-जर्मनी की पूर्वी सीमा और पोलिश कारीडार

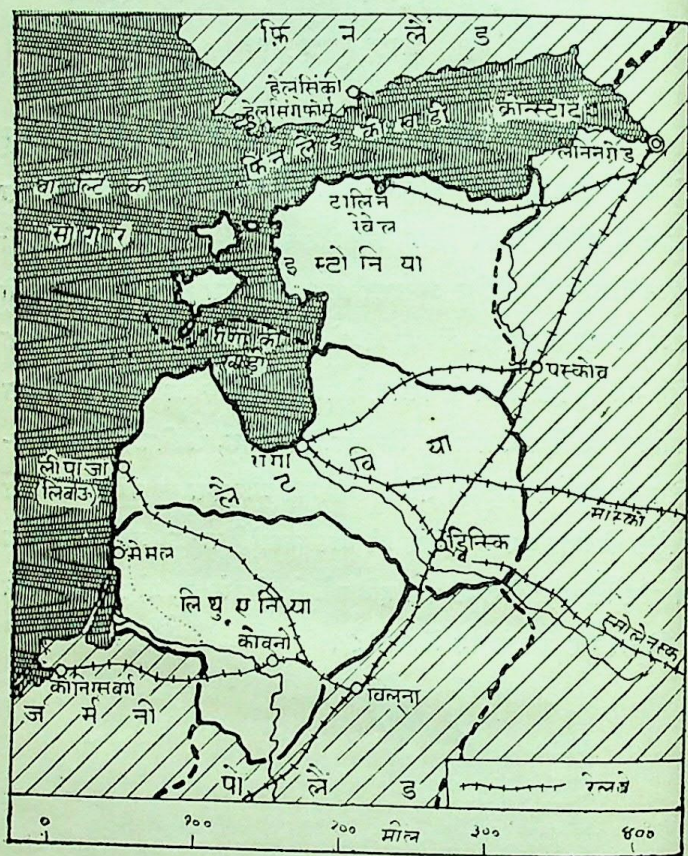
पोलिश कारीडार ५० मील चौड़ी ज़मीन की पट्टी है। पोलैंड को समुद्र तक प्रवेश-मार्ग देने के लिये यह प्रदेश बड़ी लड़ाई के बाद पोलैंड को दे दिया गया। इस पट्टी की प्रधान नदी विश्चुला है। इसके दोनों ओर पोल लोग बसे हैं। वास्तव में पोल लोग विश्चुला के निकास से मुहाने तक फैले हुए हैं। विश्चुला सब तरह से पोलैंड की नदी है। लेकिन पोलिश कारीडार जर्मनी के ईस्ट (पूर्वी) प्रशा को समूचे देश से अलग करती है और जर्मनी के पेट में छुरी की तरह भुकी हुई है। यदि समुद्र तट की एकता रक्खी जाय तो पोलैंड के साथ अन्याय होता है और पोलैंड के लोग दो भागों में बट जाते हैं। यदि नदी की एकता रक्खी जाय तो जर्मन प्रदेश दो भागों में बट जाता है। डेंज़िग बन्दरगाह में जर्मन लोगों की प्रधानता है। बड़ी लड़ाई के बाद लीग (राष्ट्र संघ) की मातहत में यह एक स्वाधीन शहर बना दिया गया। इस समय डेंज़िग का स्थानीय शासन नाज़ी दल के हाथ में है। इस बन्दरगाह से बचने के लिये पोलैंड ने गिडीनिया नाम का अपना एक अलग बन्दरगाह बनाया। गिडीनिया बन्दरगाह का व्यापार बाल्टिक तट के दूसरे बन्दरगाहों से कहीं अधिक बढ़ गया है।

जर्मनी की पूर्वी सीमा के दक्षिणी सिरे पर अपर साइलेशिया की कोयले की खानें हैं। १९२१ के लोकमत के अनुसार इस प्रदेश का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग पोलैंड को मिल गया।



५-बड़ी बड़ाई में रूस के खोये हुए प्रदेश

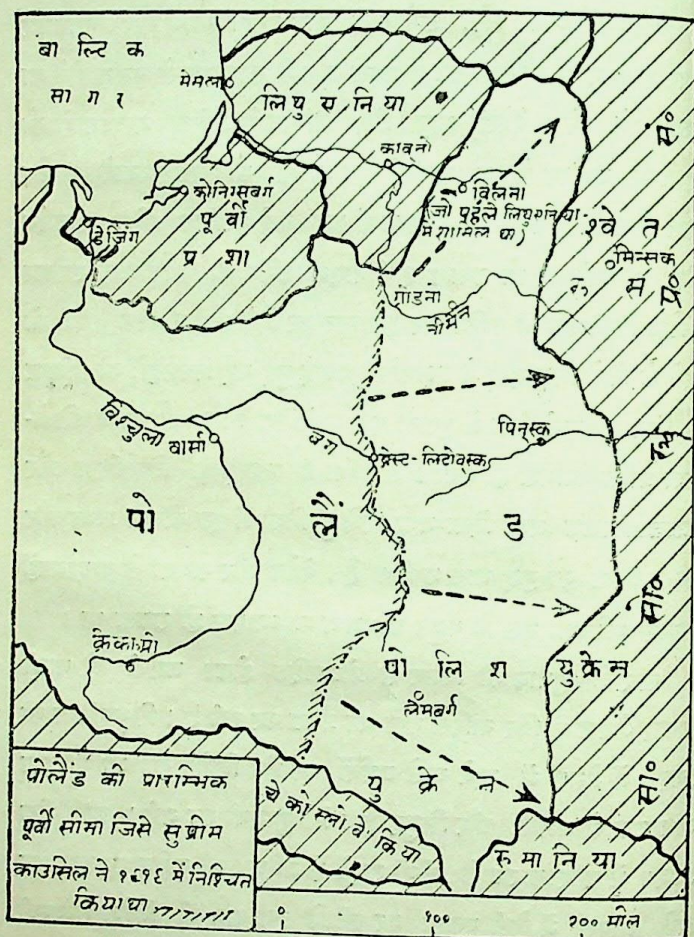
बड़ी लड़ाई में रूस हारा नहीं था। लेकिन जब यहां क्रान्ति हुई तो उसके मित्र देश रूस से नाराज़ हो गये। वसेल्स की सन्धि में रूस का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया। १९१८ में जर्मनी ने रूस के मध्ये वेस्ट-लियोव्स्क की सन्धि जबरदस्ती मढ़ी थी। इस सन्धि के अनुसार जो राज्य जर्मनी के संरक्षण में बनाये गये थे। वे अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बना दिये गये। इस प्रकार लेनिनग्रेड के पड़ोस को छोड़ कर रूस का समस्त बाल्टिक तट छिन गया और फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, और लिथुएनिया के स्वतन्त्र राष्ट्र बन गये। भीतर की ओर रूस का बहुत बड़ा भाग पोलैंड को मिल गया। दक्षिण की ओर बसारेबिया का प्रान्त रूमोनिया ने छीन लिया। फिर भी रूस हथियारों के जोर से इन प्रदेशों पर फिर से अधिकार कर लेने के पक्ष में नहीं है।



६-बाल्टिक तट की रियासतें

१९०५ ई० की रूसी क्रान्ति के बाद एस्टोनिया, लिवोनिया और कोरलैंड के रूसी बाल्टिक तट के प्रान्त ज़ार के साम्राज्य से अलग होने का प्रयत्न करने लगे। रेवेल, राइगा और लिबाउ के प्रसिद्ध बन्दरगाहों को बढ़ाने के उद्देश्य से ज़ारशाही ने इन प्रान्तों को रूसी बनाने का घोर प्रयत्न किया। १९१८ के आरम्भ में इस सारे बाल्टिक प्रदेश पर जर्मन फौजों का अधिकार हो गया। इसी समय लेनिन की साम्यवादी सरकार ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। बोल्शेविक शक्ति को घेरने के लिये मित्र दलों ने जर्मनों की बनाई हुई नई रियासतों को स्वीकार कर लिया। एस्टोनिया में पुराना पूरा एस्टोनिया प्रान्त और आधा लिवोनिया प्रान्त शामिल हो गया। लैटविया में बचा हुआ लिवोनिया और समस्त कोरलैंड मिला दिया गया। लिथुएनिया में पूरा कोवनो प्रान्त और विल्ना प्रान्त का कुछ भाग शामिल है। रेवेल और रायगा के बन्दरगाहों के द्वारा पश्चिमी रूस के बहुत बड़े भाग का व्यापार हो सकता था।

सार के चुनाव की विजय से प्रोत्साहित होकर जर्मनी की नाज़ी सरकार मेमल के फिर वापिस लेने का प्रयत्न कर रही है। लिथुएनिया की कचहरी में मेमल में रहने वाले जर्मनों पर देश विद्रोह का जो मुकदमा चला उस से जर्मनी और लिथुएनिया में दुश्मनी बढ़ गई। इसी बीच १९३४ में बाल्टिक तट के तीनों राष्ट्रों ने जनेवा की सन्धि पर हस्ताक्षर करके आपस में ऐसी एकता कर ली कि इन सब की विदेश सम्बन्धी नीति एक रहेगी।



७-पोलैंड की पूर्वी सीमा

वर्सेल्स की सुप्रीम काउंसिल (प्रधान समिति) में पोलैंड की पूर्वी सीमा उस रेखा को बनाया था जो वेस्ट लिटोव्स्क से उत्तर और दक्षिण की ओर जाती है। पोलिश यूक्रेन पोलैंड के प्रभुत्व में एक अलग स्वाधीन राज्य बनाया गया। इस सीमा के अन्दर अधिकतर पोलिश लोग रहते थे। १९२० में पोलैंड और रूस की लड़ाई के बाद पोलैंड की पूर्वी सीमा बहुत आगे बढ़ गई। इससे हाइट (श्वेत) रूसी और यूक्रेन निवासी और यहूदी लोग पोलैंड की प्रजा बन गये। पोलैंड के भूतपूर्व राष्ट्रपति पिल्सुड्स्की के शासन काल में अल्पसंख्यक पोलिश यूक्रेन के लोगों ने स्वाधीन होने के लिये लीग (राष्ट्र संघ) को अर्ज़ा दी पर इसका कोई फल न हुआ।

१९२० में पोलैंड की फौज ने लिथुएनिया पर हमला किया, और यहाँ की राजधानी विल्ना और नीमेन नदी के उत्तर वाले प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार रूस और लिथुएनिया के बीच में पोलैंड का प्रदेश घुस गया। पोलैंड की इस डकैती को लिथुएनिया ने अब तक स्वीकार नहीं किया और नीमेन नदी और मेमेख बन्दरगाह को पोलैंड के व्यापार के लिये बन्द कर दिया। राष्ट्रसंघ (लीग) ने इस भगड़े को सुलझाने की काफी कोशिश की पर इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली।

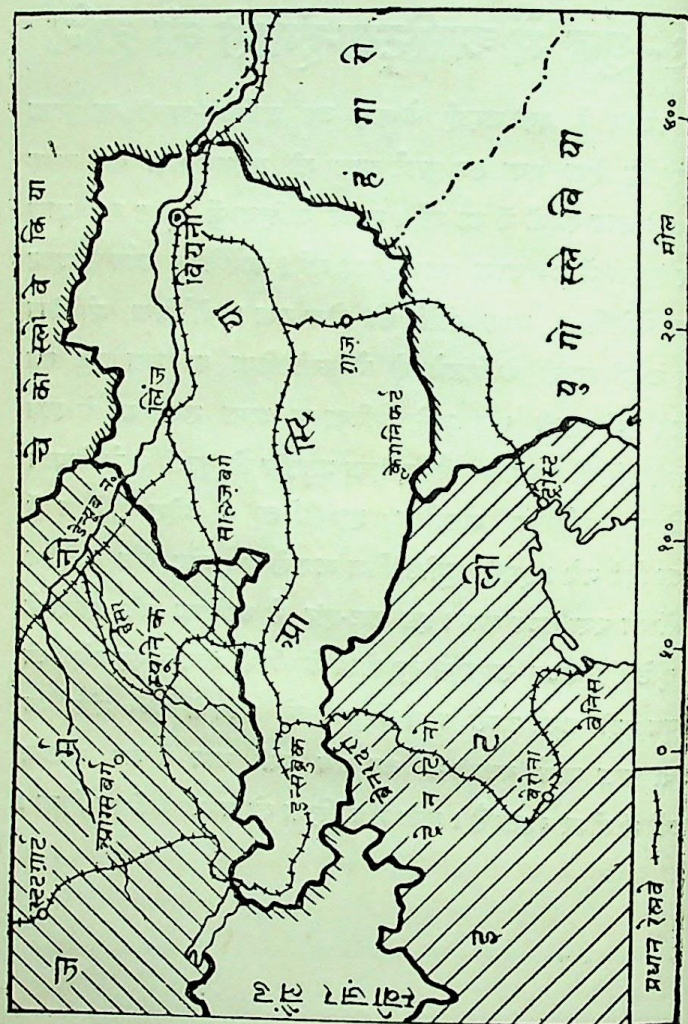
८-यूक्रेन

यूक्रेन प्रदेश में यूक्रेनियन (लघुरुसी) या रूथेनियन रहते हैं । इस प्रदेश की पेटी योरूपीय रूस के दक्षिणी भाग से आरम्भ होकर पूर्वी पोलैंड, पूर्वी चेकोस्लोवेकिया और रूमानिया (बुकोविना और बसारेविया) को छूती है । १९१८ में ब्रेस्टलिटोव्स्क की सन्धि के अनुसार रूस का यह प्रदेश स्वाधीन बना दिया गया था । रूसी क्रान्ति के बाद १९१९-२० में लाल सेना ने इस प्रदेश को फिर से जीत लिया । १९२३ में यूक्रेन का साम्यवादी सोवियट प्रजातंत्र रूस का अंग बन गया ।

यह रूस का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है । यहां की कर्नेज़म या काली मिट्टी बड़ी उपजाऊ है । यहीं डोनेट्ज़ की कोयले की खानें क्रिवोई रोग की लोहे की प्रसिद्ध खानें हैं । यहीं कीव और खारकोव के कारबारी नगर और काले सागर के तट पर बसे दुष्ट ओडेसा, रोस्टोव, नोवोरोसिस्क के व्यापारिक बन्दरगाह हैं । यूक्रेन का राष्ट्रीय आन्दोलन इस समय पश्चिमी योरूप और अमरीका में निर्वासित लोगों तक ही सीमित है ।

६-युद्ध में आस्ट्रिया-हंगरी की हानि

१९१६ में बड़ी लड़ाई के बाद जब आस्ट्रिया-हंगरी का पुराना राज्य तोड़ दिया गया तब पुराने राज्य को लगभग सवा पाँच करोड़ आबादी सात राज्यों में बंट गई। नवीन आस्ट्रिया में केवल ६५ लाख और हंगरी में ८० लाख आबादी रह गई। कार्पेथियन पर्वत के उत्तर वाला गेलिशिया प्रान्त पोलैंड को मिल गया। बोहेमिया, मोरेविया और उत्तरी हंगरी के मिलने से चेकोस्लोवेकिया का नया राष्ट्र बन गया। पूर्वी हंगरी और ट्रान्सिल्वेनिया का प्रान्त रूमानिया के हाथ लगा। दक्षिणी टायरोल और इस्ट्रिया प्रायद्वीप को इटली ने ले लिया। क्रोशिया, डल्मेशिया, बोसनिया, हर्ज़ोगोविना के प्रदेश सर्बिया में मिला दिये गये। इससे यूगोस्लैविया नाम से सर्व, क्रोट और स्लोवीन लोगों का नया राज्य बना। इस काट-छांट से आस्ट्रिया और हंगरी के दो छोटे छोटे राज्य समुद्र से दूर योरोप के भीतरी भाग में पड़ गये। जो डेन्यूब नदी अपने ऊपरी मार्ग में पुराने बड़े राज्य में ७०० मील का लम्बा जल मार्ग बनाती थी वह अब उसी भाग में चार स्वतन्त्र राज्यों में होकर बहती है। हाल में आस्ट्रिया को जर्मनी ने मिला लिया।



88/89

१०-आस्ट्रिया

नवीन आस्ट्रिया की राजधानी वियना में २० लाख और शेष देश के पहाड़ी भाग में ४५ लाख मनुष्य रहते हैं। शहर के लोग साम्यवादी विचार के हैं। देहात के किसान लोग परम्परा त्रेमो रोमन कैथलिक हैं। वैसे देश में प्रायः ६७ फी सदी लोग जर्मन भाषा-भाषी हैं और जाति, भाषा और संस्कृति में अपने उत्तरी पड़ोसी जर्मन लोगों के ही अंग हैं। बड़ी लड़ाई की काट-छांट से आस्ट्रिया की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय हो गई। पिछले १५ वर्षों में आस्ट्रिया को दीवालिया होने से बचाने के लिये राष्ट्र संघ (लीग) और दूसरी संस्थाओं को आस्ट्रिया की सहायता करनी पड़ी।

दक्षिण में फेसिस्ट इटली और उत्तर में नाज़ी जर्मनी के बीच में आस्ट्रिया की भौगोलिक स्थिति खतरे से खाली नहीं थी। पहले ब्रिटेन, फ्रांस और इटली देश आस्ट्रिया की स्वाधीनता कायम रखने के लिये वचनबद्ध थे। लेकिन गत वर्ष जर्मनी ने फौजी प्रदर्शन करके बिना आक्रमण किये ही आस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इस समय आस्ट्रिया जर्मनी का ही अंग है। स्वाधीन आस्ट्रिया योरुप के नक्शे से अचानक उड़ गया।

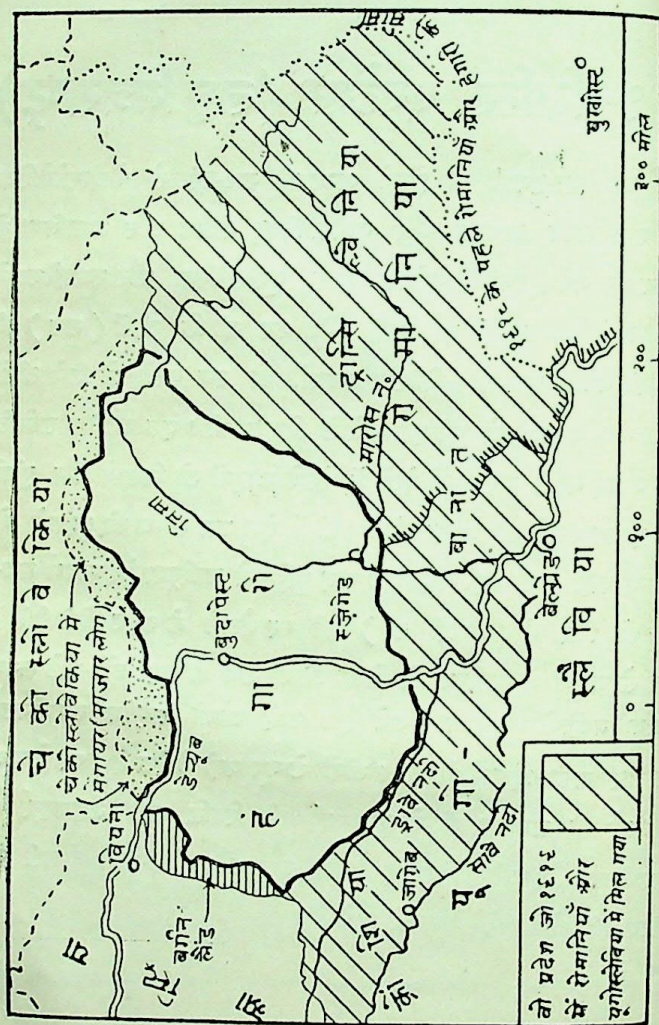
पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ा

[२१]

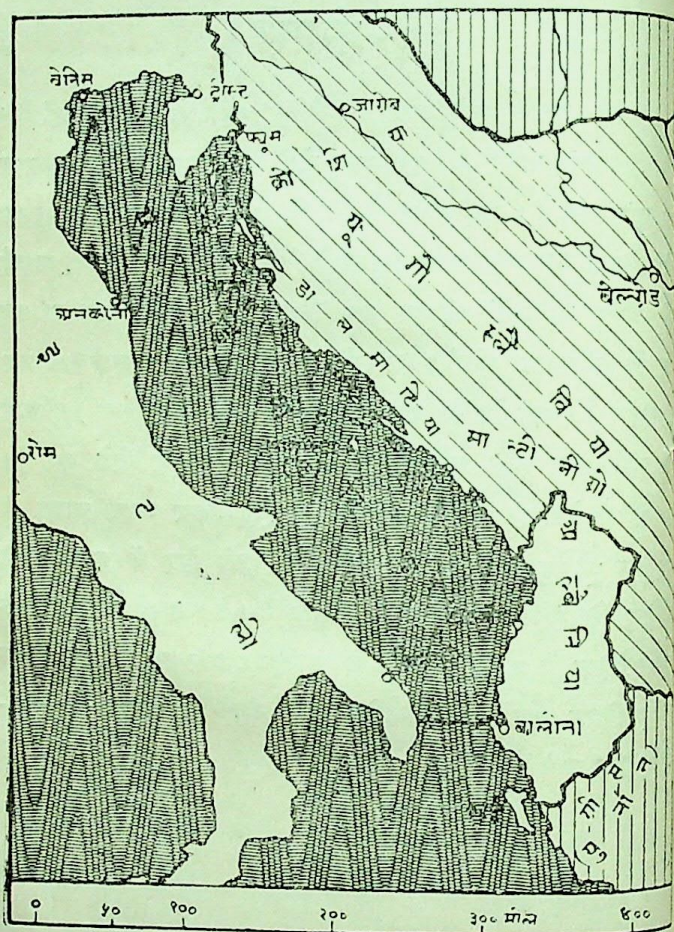
११-लिटिल एण्टेण्ट (लघु मित्रराष्ट्र)

आस्ट्रिया-हंगरी के पुराने राज्य की काट-छांट से चेकोस्लोवेकिया का नया राज्य बन गया और यूगोस्लैविया, पोलैंड और रूमानिया के राज्य बढ़ गये। इन में चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लैविया और रूमानिया ने १९३३ में आपस में एक ऐसी सन्धि कर ली कि तीनों (सब) की विदेशी नीति एक रहे। विदेशी मामलों को तय करने के लिये तीनों देशों ने तीन सन्धियों की एक समिति नियुक्त की। एक आर्थिक समिति भी बनाई गई। यह तीनों देशों में रेलवे लाइनों को मिलाने और चुंगी की एकता रखने का प्रयत्न करेगी। तीनों देश उस सन्धि को दुहराने के पक्ष में नहीं हैं जो बड़ी लड़ाई के बाद हुई। वे आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग राज-वंश को फिर से (हंगरी की) गद्दी पर बैठाने के कट्टर विरोधी हैं। जब से जर्मनी ने आस्ट्रिया को मिला लिया तब से यह छोटे-छोटे राज्य जर्मन नाज़ियों से घबराते लगे हैं। उन्हें अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता को भारी संकट दिखाई देता है। तीनों डैन्यूब नदी के देश हैं। पर डैन्यूब के मार्ग के सम्बन्ध में डैन्यूब नदी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है रूमानिया और यूगोस्लैविया के प्रधान जल और रेल-मार्ग हंगरी में होकर ही चेकोस्लोवेकिया को जाते हैं।



१२-हंगारी

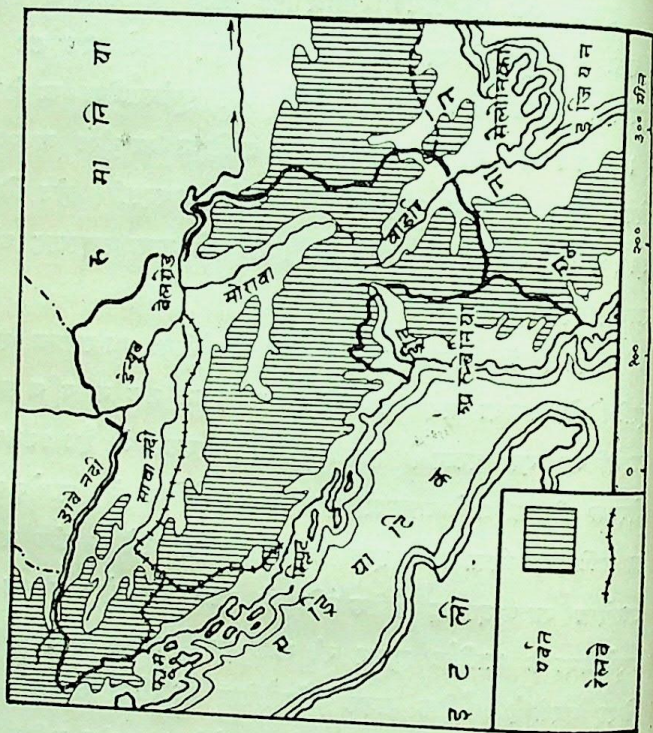
नवीन हंगारो एक राज्य है। लेकिन वहां कोई राजा नहीं है। राज सिंहासन खाली है। एडमिरल होर्दी नाम मात्र के लिये युवराज का काम करते हैं। इस प्रकार हंगारी के लोग प्रगट रूप से १९१९ की सन्धि से नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने बड़ी लड़ाई की सन्धि की शर्तों की बार बार निन्दा की। समय आने पर वह बल का भी प्रयोग करेगी। इस सन्धि से लगभग एक तिहाई मेगायर (माजार) हंगारी देश के बाहर रूमानिया (ट्रान्सिल्वेनिया) दक्षिणी चेकोस्लोवेकिया और यूगोस्लैविया (बानात) में कर दिये गये हैं। हंगारी के नेता हंगारी देश की सीमा को इस प्रकार बढ़ाना चाहते हैं कि यह छूटे हुए माजार लोग फिर से हंगारी देश में आजावें। वे ट्रान्सिल्वेनिया में स्वाधीन राज्य चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि यूगोस्लैविया के क्रोट, बर्गेनलैंड के आस्ट्रियन और पूर्वी चेकोस्लोवेकिया के यूक्रेनियन लोगों का राजनैतिक भाग्य उनके ही बहुमत से निर्धारित किया जावे।



१३-इटली, यूगोस्लैविया और एड्रियाटिक

इटली देश एड्रियाटिक सागर को अपने अधिकार में रखना चाहता है। यूगोस्लैविया अपने नये मिले हुए डलमेशियन तट को सुधारना चाहता है। इसी से इटली और यूगोस्लैविया का विरोध है। १९१९ की सन्धि से इटली को आस्ट्रिया का ट्रीस्ट बन्दरगाह मिल गया। फ्र्यूम बन्दरगाह को उसने ज़बरदस्ती छीन लिया १९२० की रपालो की सन्धि से इटली को ज़ारा बन्दरगाह और लागोस्टा द्वीप मिल गया।

१९१३ में बाल्कन युद्ध के बाद अल्बेनिया का स्वतन्त्र राज्य इसी लिये बनाया गया कि सर्बिया समुद्र-तट तक न पहुँच सके। अल्बेनिया एक प्रकार से इटली की ही संरक्षकता में है। १९२६ में तिराना की सन्धि के अनुसार इटली को अल्बेनिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। इटली के दक्षिणी-पूर्वी सिरे के ठीक सामने वालोना का बन्दरगाह सैनिक दृष्टि से इटली के बड़े काम का है। अल्बेनिया के आर्थिक सुधार की सभा का नियन्त्रण इटली के बैंक किया करते हैं। सैनिक सड़कें यूगोस्लैविया की सीमा तक बन चुकी हैं। एड्रियाटिक सागर में इटली और अल्बेनिया का ठीक वही सम्बन्ध है जो केरिबियन सागर में संयुक्तराष्ट्र अमरीका और क्यूबा का है। हाल में इटली और यूगोस्लैविया का सम्बन्ध कुछ सुधर गया है।

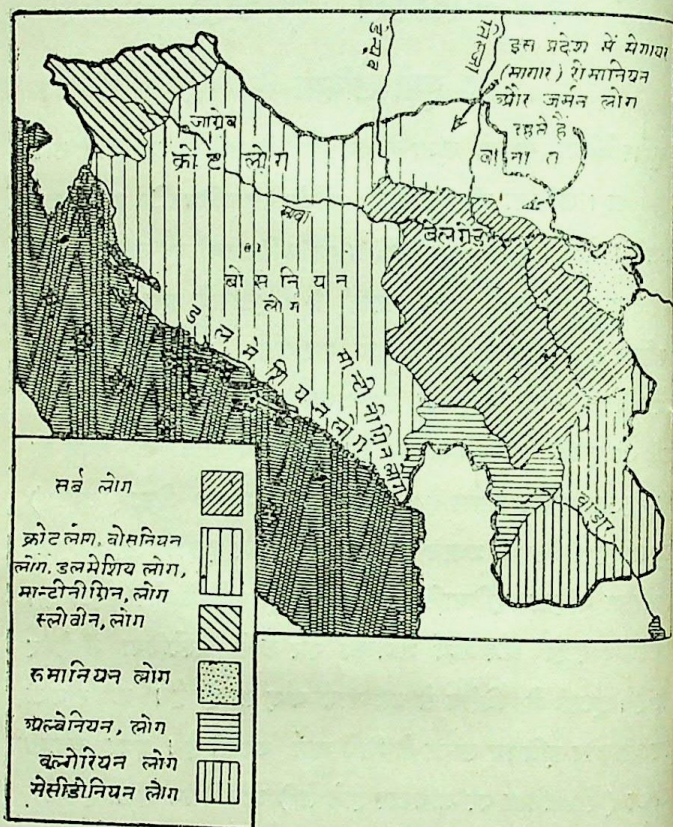


पूरा
पहुँच
यूगों
तक
प्र
फ्यूम
बाहर
में पड़े
और
डीन
बहती
दक्षिण
लोगों

१४—लिटिल एण्टेण्ट

१ यूगोस्लैविया

यूगोस्लैविया के नये राज्य के बन जाने से सर्बिया का पुराना स्वप्न पूरा हो गया। सर्बिया की बड़ी इच्छा थी कि वह एड्रियाटिक सागर तक पहुँच सके। लेकिन इससे यूगोस्लैविया को कठिनाइयाँ दूर नहीं हुई हैं। यूगोस्लैविया का पश्चिमी भाग पहाड़ी है। इसलिये इस ओर समुद्र तक पहुँचने में बड़ी बाधा है। देश को पार करके समुद्र-तट तक केवल दो प्रधान रेलवे लाइनें पहुँचती हैं। उत्तरी शाखा का अन्तिम स्टेशन फ्यूम है जो इटली के अधिकार में है। यूगोस्लैव लोगों को फ्यूम का बाहरी मुहल्ला सूसक मिला है। दक्षिणी रेलवे शाखा स्प्लिट (स्प्लिट) में पहुँचती है। देश की प्रधान नदी डैन्यूब और इसकी सहायक ड्रावे और मोरावा नदियाँ एड्रियाटिक सागर से दूर पूर्व की ओर बहती हैं। ड्रीन घाटी दक्षिणी और मध्य भाग को पार करके अल्बेनिया में होकर बहती है। इटली के विरोध से यह मार्ग बन्द सा ही है। वार्डार घाटी दक्षिण की ओर इजियन सागर के लिये मार्ग बनाती है। इधर यूनानी लोगों का (सेलोनिका पर अधिकार होने से) घोर विरोध होता है।



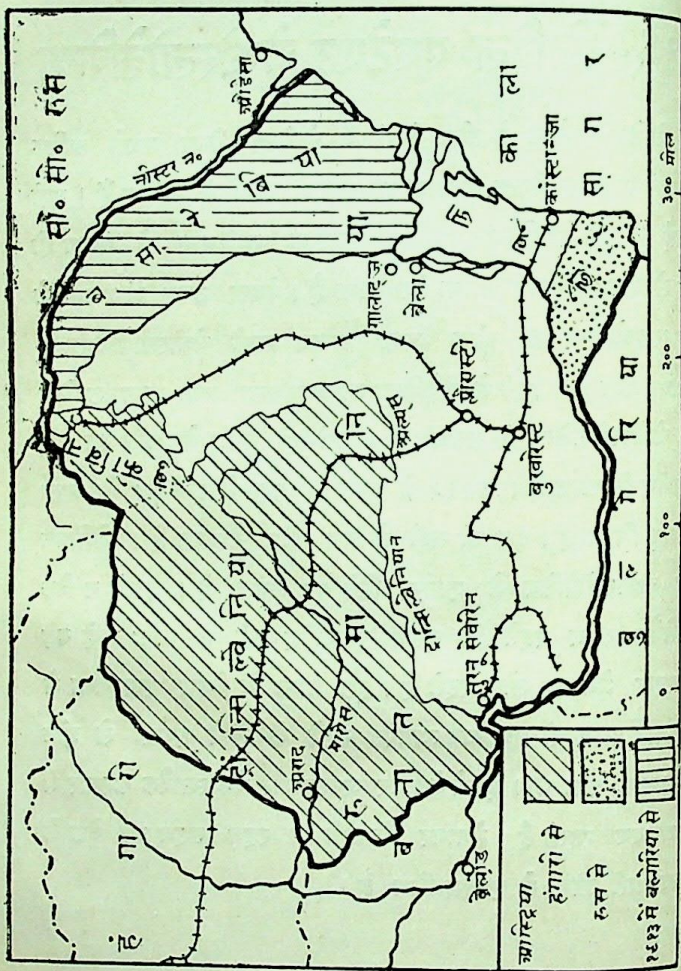
१५—यूगोस्लैविया की जातियाँ

यूगोस्लैविया सर्व, क्रोट और स्लोवीन लोगों का राज्य है पुरानी सर्बिया के बहुत कुछ बढ़ जाने से यह राज्य बना है। १९१२-१३ के बाल्कन युद्ध के बाद सर्बिया का प्रदेश दक्षिण में वार्डर घाटी की ओर काफी बढ़ गया। १९१९ में बड़ी लड़ाई के बाद आस्ट्रिया हंगरी के स्लोवानिक प्रान्त (क्रोशिया, स्लैवानिया बोस्निया, हार्जी गोब्रिना और और मान्टीनीग्रो का छोटा राज्य सर्बिया में मिला दिया गया। इन सब के मिलने से यूगोस्लैविया का राज्य बना है। सर्व लोग इन नये प्रान्तों को अपने अधिकार में समझने लगे हैं। सर्व लोगों से अधिक सभ्य और कारवारी क्रोट लोग इसका विरोध करते हैं और अपने लिये स्वाधीनता चाहते हैं। क्रोट लोग कैथालिक हैं। सर्व लोग आर्थोडॉक्स चर्च के ईसाई हैं।

देश के भीतरी विग्रह को सुलझाने के लिये सर्बिया के राजा एलेग्ज़ेंडर ने नये ढंग की लोकमतसत्ता स्थापित की। इसके अनुसार देश में एक ही राष्ट्रीय दल को स्थान दिया गया। वह स्वयं डिक्टेटर या तानाशाह बन गया। लेकिन उसकी हत्या कर डाली गई। राजा के मारे जाने के बाद देश के सामने नई समस्या उपस्थित हुई। युवराज की सभा सर्बिया की एकता भी रखना चाहती है। इसके साथ ही क्रोशियन लोगों की मांगों को पूरा करना भी जरूरी है।

१६—लिटिल एण्टेण्ट चेकोस्लोवेकिया

लिटिल एण्टेण्ट के तीन देशों में चेकोस्लोवेकिया सबसे अधिक कारबारी है। स्वाधीनता के भाव भी यहाँ के लोगों में अधिक हैं। बड़ी लड़ाई के बाद आस्ट्रिया-हंगरी के राज्य के बड़े भाग के अलग हो जाने से प्रायः चेकोस्लोवेकिया देश बना है। केवल उत्तर में जर्मनी से अपर साइलेशिया का छोटा ज़िला अलग करके चेकोस्लोवेकिया में मिलाया गया है। इसी में बोहेमिया का घना बसा हुआ प्रान्त शामिल है। चेकोस्लोवेकिया में लगभग ७० फ़ीसदी लोग चेक और स्लोवैक, २० फ़ीसदी जर्मन हैं। १९३५ के चुनाव में यहाँ के नाजीदल को अपूर्व सफलता मिली है। दस फ़ीसदी मेगायर और रुथेनियन हैं। रुथेनियन प्रान्त चेकोस्लोवेकिया के एकदम सिरे पर स्थित है। इसमें न चेक न स्लोवैक लोग रहते हैं। इसमें पुरानी हंगरी के प्रायः बड़े बड़े जागीरदार मेगायर लोग रहते हैं। इस प्रान्त को केवल रूमानिया से अटूट मार्ग सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये हंगरी से छीन कर मिलाया गया था। इससे मेगायर जनता और चेकोस्लोवैक सरकार में बड़ी अनबन रहती है। मेगायर किसानों का रहन सहन भी देश के चेक कारबारी लोगों से एकदम भिन्न है।



१७—लिटिल एण्टेण्ट रूमानिया

बड़ी लड़ाई के बाद रूमानिया देश पहले से दुगने से भी अधिक बढ़ गया है। इसी लिये रूमानिया बड़ी लड़ाई से सम्बन्ध रखने वाली सन्धियों को दुहराने (सुधारने) के लिये तैयार नहीं है। यह प्रायः खेतिहर देश है। कई नये भागों के मिल जाने से रूमानिया में कई जातियों का जनघट हो गया है। रूमानियन लोगों के अतिरिक्त यहाँ लगभग ढाई लाख यूक्रेनियन, ढाई लाख जर्मन और यहूदी और दस लाख मेगायर (माजार) दो लाख बल्गेरियन और दो लाख तुर्की और तारतार रहते हैं।

यूक्रेनियन लोग वसारेबिया प्रान्त में रहते हैं। इस प्रान्त को रूमानिया ने क्रान्ति के समय १९१६ ई० में रूस से छीन लिया था। बुकोविना प्रान्त पहले आस्ट्रिया के सम्राट की सम्पत्ति थी। माजार लोग अधिकतर ट्रान्सिल्वेनिया, और बानात में रहते हैं। डोब्रूजा प्रान्त का दक्षिणी भाग १९१३ ई० में दूसरे बाल्कन युद्ध के बाद रूमानिया ने बल्गेरिया से छीन लिया था। नाज़ी कारनामों से रूमानिया में फिर यहूदी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है।

रूमानिया का प्रधान निर्यात गेहूँ और मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल के चश्मे अधिकतर ट्रान्सिल्वेनियन अल्पास के दक्षिणी ढालों पर पाये जाते हैं।

१८—बल्गेरिया

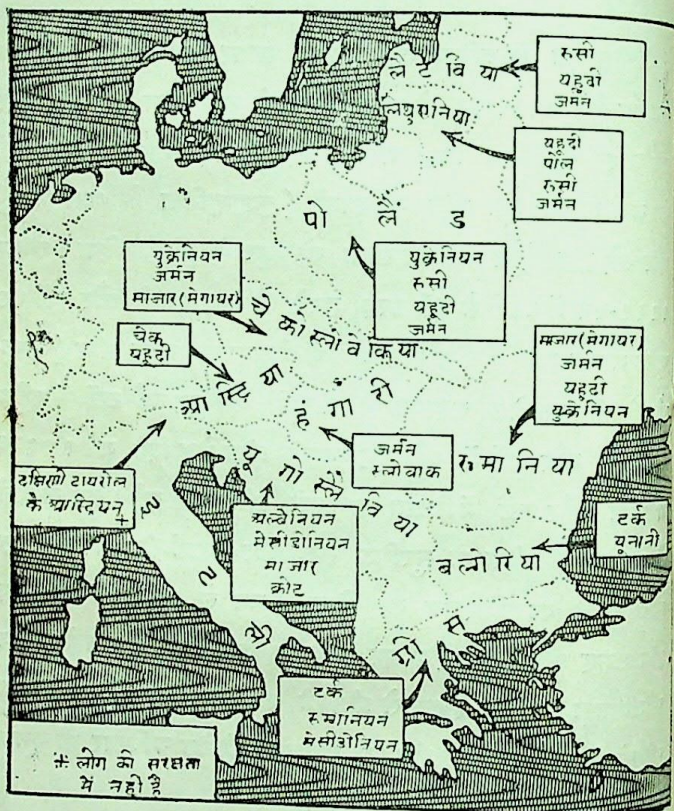
बल्गेरिया को अक्सर बाल्कन प्रदेश का हंगारी कहते हैं। हंगारी १ तरफ बल्गेरिया भी १९१८ की सन्धि से असन्तुष्ट है। वह इसको यथाशीघ्र बदलवाना चाहता है। इससे पहले १९१३ ई० की सन्धि पे भी उसे घोर असन्तोष है। १९१२ में बल्गेरिया अपने सब पड़ोसियों से अधिक बलवान था। १९१३ ई० में जब उसने अपने पड़ोसी मित्रों से मिलकर टर्की को हराया तो उसे कोई विशेष लाभ न हुआ। १९१३ में सर्बिया ने मेसीडोनिया और ग्रीस (यूनान) ने सेलोनिका ले लिया। रूमानिया ने उत्तर की ओर दक्षिणी डोब्रूजा प्रदेश ले लिया बल्गेरिया को ईजियन सागर के किनारे का कुछ भाग मिला। वह भी १९१८ में उस से छीन लिया गया।

यूगोस्लैविया से स्थायी शत्रुता रखना ही बल्गेरिया की विदेशी नीति मालूम होती है। लेकिन डांग नाच ओस्टन (नाज़ी) जर्मनी के डर से शायद दोनों देशों में कुछ मित्र भाव हो जावे।

रूमानिया की तरह बल्गेरिया के लोग भी अधिकतर किसान हैं। वे अपनी सरकार से बहुत ही असन्तुष्ट हैं। उनको दवाने के लिये तरह-तरह के कानून बने। हाल में फौजी अफसरों और राजा बोरिस के बीच में जो दांव पेंच चले उससे सम्भव है कि नया शासन-सुधार अधिक सन्तोष जनक हो।

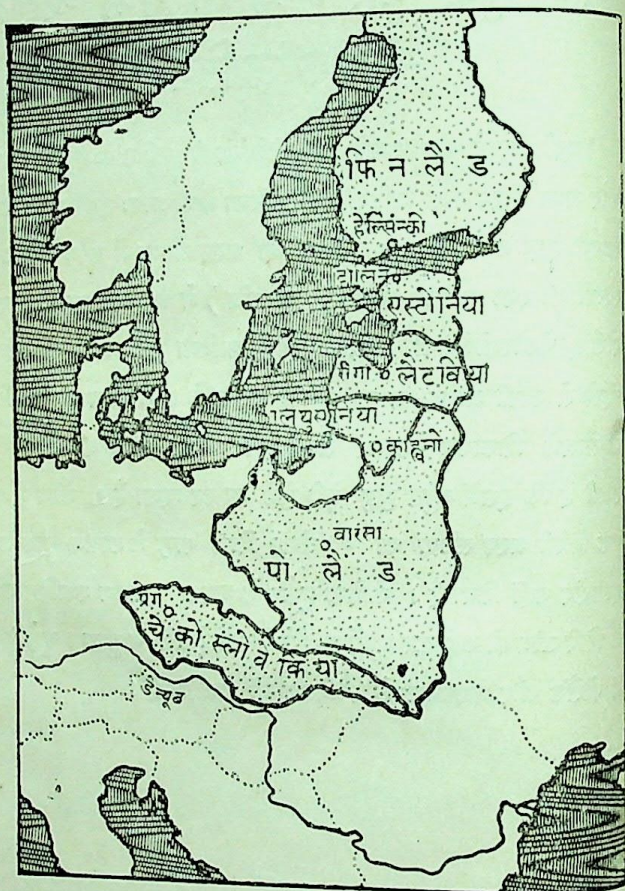
१६-ग्रीस (यूनान)

ग्रीस देश में अधिक तर ईजियन सागर का तट और कुछ द्वीप शामिल है। १६१२-१३ के बाल्कन युद्ध के बाद ग्रीस को कुछ उत्तरी तट और सेलोनिका मिल गया। बड़ी लड़ाई के बाद मित्र राष्ट्रों ने टर्की से पूर्वी थ्रेस छीन कर स्मर्ना (कुस्तुन्तुनिया के पास तक) और कई द्वीप देकर ग्रीस की सीमा को बहुत कुछ बढ़ा दिया। लेकिन १६२१-२२ में टर्की से बुरी तरह हारने के बाद स्मर्ना और पूर्वी थ्रेस चला गया। हाल में ग्रीस और टर्की में मित्रता हो गई। लीग (राष्ट्र-संघ) की आर्थिक सहायता से ग्रीस में बसे हुए टर्क टर्की में पहुँचा दिये गये और टर्की में बसे हुए यूनानी ग्रीस भेज दिये गये। १६३३ में ग्रीस और टर्की में मित्रता सम्बन्धी सन्धि हो गई। इस से दोनों ने आपस की सीमा को सुरक्षित रखने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर एक मत रखने का निश्चय कर लिया। जब से इटली ने डोडेकनीज़ द्वीप समूह और र्होड द्वीप पर अधिकार कर लिया और वहाँ अपना फौजी अड्डा बनाया है तब से ग्रीस की राष्ट्रीय भावनायें कुछ विफल सी हो गई हैं। साइप्रस द्वीप पर लगातार ब्रिटिश अधिकार भी यूनानी राष्ट्रीय सम्मान को धक्का पहुँचाता है।



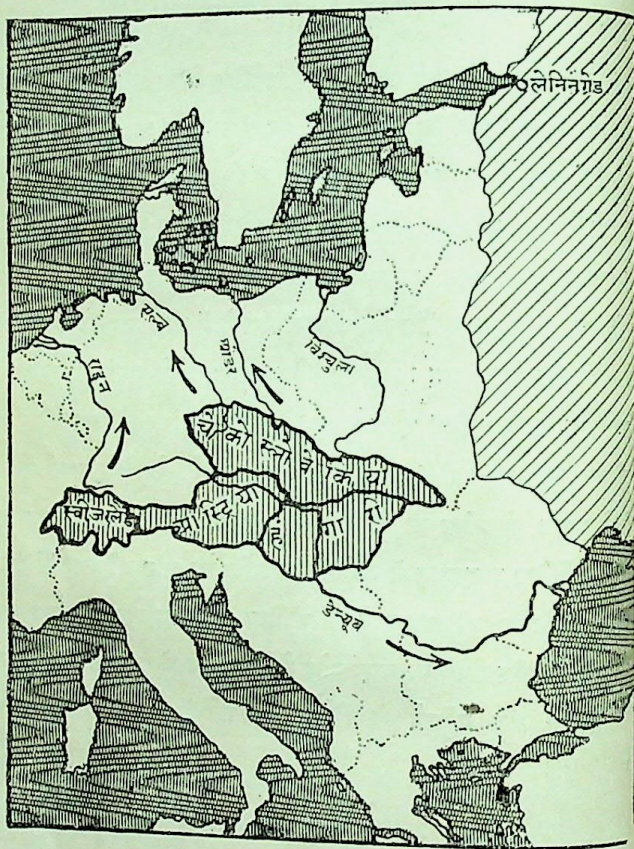
२०-पूर्वी और मध्य योरुप में अल्प- संख्यक जातियां

बड़ी लड़ाई और उसके बाद होने वाली सन्धि के अनुसार पूर्वी और मध्य योरुप में जो जातियाँ अल्प संख्या में थीं प्रायः उन सब ने अलग अलग राष्ट्र बना लिये । इनके यहां जो अल्प संख्या में लोग बचे उनके स्वत्वों की रक्षा का भार लीग (राष्ट्र संघ) ने अपने ऊपर ले लिया । पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लैविया, रूमानिया और ग्रीस की सीमायें पहले से काफी अधिक बढ़ गईं । अल्प संख्या के लोग लीग की काउंसिल के सामने शिकायत पेश कर सकते हैं । लेकिन लीग की प्रथा ऐसी ढीली है कि इसमें बहुत कुछ देरी होने का डर रहता है । लीग ने अब तक किसी अल्प संख्या का पक्ष लेकर किसी राष्ट्र के शासन प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं किया है । पोलिश यूक्रेन ने अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिये लीग को कई बार अर्जी दी । लेकिन कोई फल न हुआ । यूक्रेनियन में पोलैंड और रूमानिया के रूथेनियन भी शामिल हैं ।



२१-योरुप के नये राष्ट्र

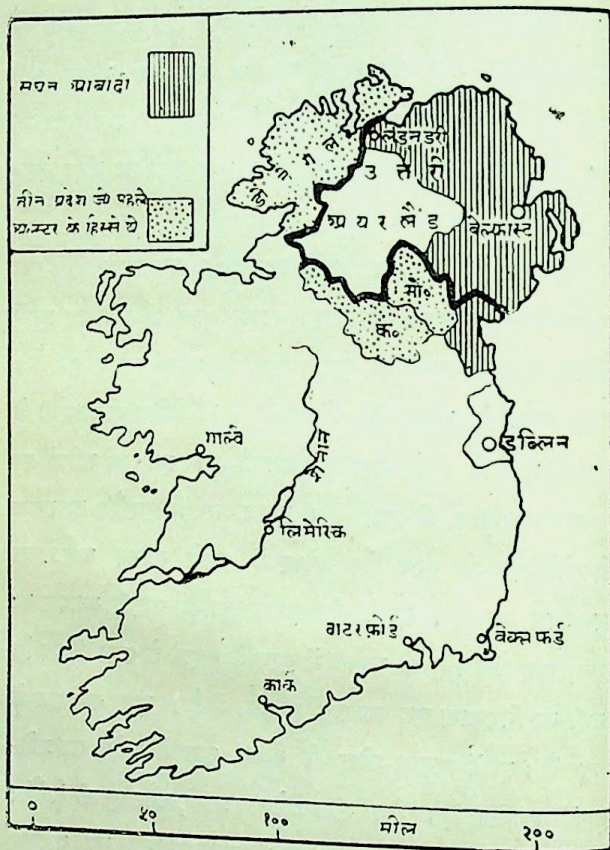
बड़ी लड़ाई के बाद योरुप की राजनैतिक सीमाओं में घोर परिवर्तन हो गया। १९१९ में छः नये और स्वाधीन राष्ट्र बन गये। इन नये राष्ट्रों के बनाने में ऊपर से राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का पालन दिखलाया गया। ऐसा करना मित्र राष्ट्रों के लिये सुविधाजनक था। नये छः राष्ट्रों में चार राष्ट्र एकदम रूस के प्रदेश को अलग कर के बनाये गये। पांचवे राष्ट्र अर्थात् पोलैंड को फिर से बनाने में भी रूस का बहुत बड़ा भाग अलग किया गया। चेकोस्लोवेकिया प्रायः पुराने आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने से बना है। प्रथम पांचराष्ट्रों का समुद्र तक पहुँचना सुगम है। पोलैंड को समुद्र तक पहुँचने के लिये मार्ग देने के लिये जर्मन के प्रदेश को दो भागों में बाँट कर पोलिश कारीडार बनाया गया। डेन्जिग बन्दरगाह में जर्मनों की अधिकता और बहिष्कार से बचने के लिये पोलैंड की सरकार ने गिडोनिया नाम का एक नया बन्दरगाह बनाया। चेकोस्लोवेकिया चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। विदेशी समुद्र-तटों तक पहुँचने के लिये इसे नदियों की सहायता लेनी पड़ती है।



२२—योरुप के भीतरी राज्य

बड़ी लड़ाई के पहले योरुप में स्विज़रलैंड और सर्बिया ही दो ऐसे भीतरी देश थे जो किसी समुद्र को नहीं छूते थे। बड़ी लड़ाई के बाद आस्ट्रिया हंगरी और चेकोस्लोवेकिया तीन और देश भीतर डाल दिये गये। वे किसी समुद्र को नहीं छूते हैं। रूस का समुद्र तट भी बहुत कम हो गया। फिनलैंड की खाड़ी के पास वाले तट को छोड़कर शेष तट रूस के हाथ से जाता रहा।

हर किसी राज्य के लिये जलमार्गों का होना आवश्यक है। कुछ नदियों को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व मिल गया। राइन, एल्ब और ओडर इनमें प्रधान हैं। यह तीनों जर्मनी की प्रधान रूप से जर्मनी की नदियां हैं। डेन्यूब नदी जर्मनी के दक्षिण में निकलती है। लेकिन वह जर्मनी के दक्षिण वाले देशों के लिये जल-मार्ग बनाती है। इन सब नदियों पर कुछ न कुछ अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण है। इस प्रकार स्विज़रलैंड को राइन में चेकोस्लोवेकिया को एल्ब और ओडर में अपने स्टीमर चलाने का अधिकार मिल गया है। इससे चेकोस्लोवेकिया के बाहरी व्यापार का प्रधान बन्दरगाह हेम्बर्ग है जो जर्मनी में एल्ब के मुहाने के पास स्थित है। डेन्यूब नदी का नियन्त्रण एक कमीशन के हाथ में है। इस कमीशन के सदस्य चार हैं। इनमें बाल्कन प्रदेश के केवल रूमानिया देश का प्रतिनिधि इसमें शामिल है। शेष तीन ब्रिटेन, फ्रांस, और इटली के हैं। बाल्कन प्रदेश के नहीं हैं। इस तरह बाहर की बड़ी शक्तियों को बाल्कन प्रदेश के झगड़ों में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता रहता है।

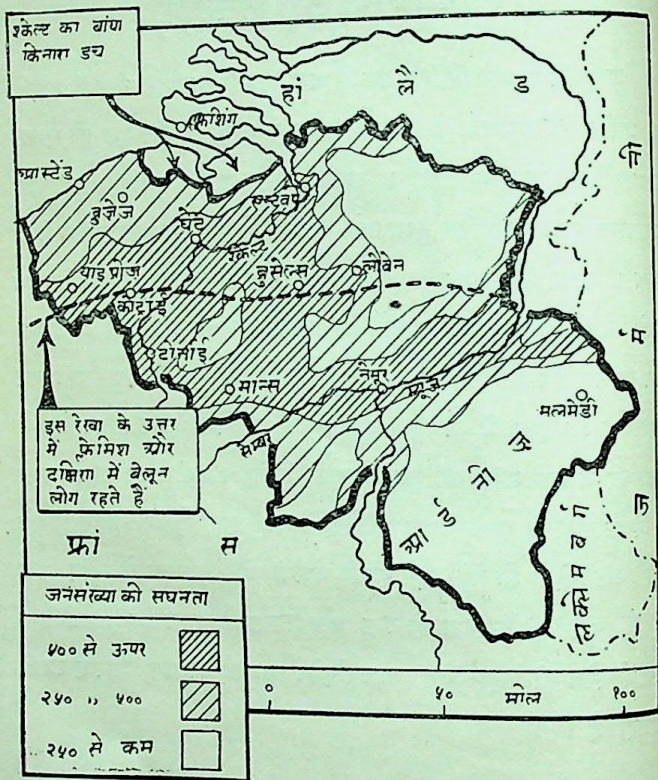


२३—आयरलैंड

उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन से आये हुए प्रोटेस्टेंट लोगों की अधिकता है। द्वीप के शेष बड़े भाग में यहाँ के असली देशवासी केथलिक लोगों की अधिकता है। केथलिक लोगों का राष्ट्रीयदल ब्रिटेन से अलग होकर एक पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित करना चाहता है। उत्तर के अल्प संख्यक लोग ब्रिटिश पार्ल्यामेंट से सम्बन्ध रखना चाहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिये उत्तरी आयरलैंड एक अलग देश बना दिया गया। इसकी पार्ल्यामेंट भी अलग कर दी गई। आयरलैंड के केथलिक लोगों को फ्रीस्टेट के नाम से एक स्वाधीन राज्य बना दिया गया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। उत्तरी प्रदेश के अलग हो जाने से घना बसा हुआ और कारबारी प्रदेश अलग हो गया। इस में सारे देश की एक तिहाई आबादी संयुक्तराष्ट्र अमरीका में जाकर बस जाती थी। लेकिन अब अमरीका ने अपना दरवाज़ा बन्द सा कर लिया है। इधर ब्रिटेन और आयरलैंड की पुरानी दुश्मनी में किसी तरह की कमी न होने के कारण ब्रिटेन के बाज़ारों में आयरलैंड का मक्खन और खेती का दूसरा सामान आज़ादी से नहीं बिक पाता है। इस लिये आयरलैंड के राष्ट्रपति के सामने विकट आर्थिक समस्या है कि द्वीप की बढ़ती हुई आबादी को किस प्रकार भोजन प्रदान किया जावे। आर्थिक दृष्टि से द्वीप को स्वावलम्बी बनाने के लिये पांच लाख एकड़ के बड़े बड़े खेतों और चरागाहों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर किसानों को देने का विचार हो रहा है। आयरलैंड के किसानों को ज़मीन की बड़ी ज़रूरत है।

२४-स्पेन का विच्छेद

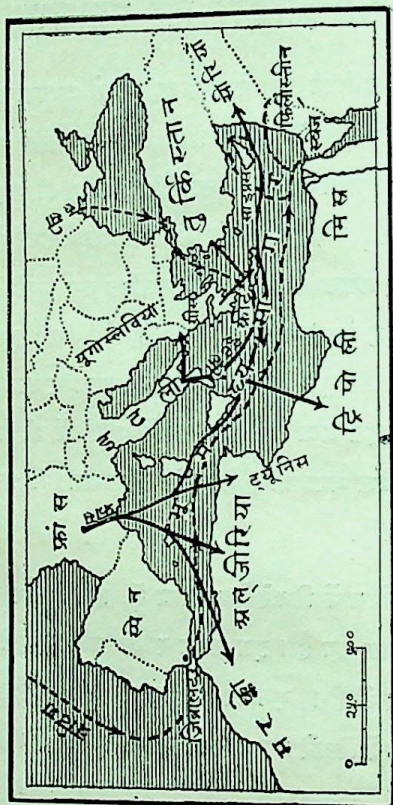
आइबेरिया प्रायद्वीप का सब से बड़ा भाग स्पेन है। स्पेन में नदियों की घाटियों और पठारों के बीच में पहाड़ खड़े हुये हैं और देश की एकता में प्राकृतिक बाधा डालते हैं। राजा के चले जाने के बाद देश में जो प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हुआ उसे प्रबल होने का पूरा अवसर न मिल सका। उत्तर में बास्क और पूर्व की ओर भूमध्य सागर के पास रहने वाले केटेलन लोग स्वाधीन होने का प्रयत्न करने लगे। नया प्रजातन्त्र जन साधारण और किसानों के आर्थिक कष्टों को कुछ भी दूर नहीं कर पाया था कि इतने में बड़े बड़े जागीरदारों, पादरियों और सेनापतियों ने मिलकर जनरल फ्रांको की अध्यक्षता में विद्रोह का झंडा उठाया। मरको में स्थित स्पेन के मूर सिपाही विद्रोहियों का साथ देने के लिये बुलाये गये। विद्रोहियों को छिपे छिपे इटली जर्मनी, और पुर्चगाल से मदद मिल रही है। स्पेन की सरकार को रूस और फ्रान्स से सहायता मिलती है। इसी से स्पेन की गृह-कलह अन्तर्राष्ट्रीय लड़ाई का रूप धारण करती जा रही है।



२५--बेल्जियम की जातियाँ

बेल्जियम के दक्षिणी बड़े भाग में रहने वाले वालून लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। उत्तरी भाग में रहने वाले फ्लेमिंग लोग डच लोगों से मिलती जुलती लो जर्मन भाषा बोलते हैं। भाषा की लड़ाई एक बार इतनी बड़ी कि बड़ी लड़ाई के समय में फ्लेमिश नेताओं ने जर्मनी की छत्र-छाया में एक अलग स्वाधीन राज्य स्थापित करने की कोशिश की। बड़ी लड़ाई के बाद वालून लोगों ने फ्लेमिश लोगों की इन हरकतों को देशद्रोही ठहराया और कुछ लोगों को दंड देने का निश्चय किया गया। इस से बड़ा कोलाहल मचा। लेकिन फ्लेमिश लोगों की भाषा को राज्य सभा में स्थान मिल गया और घेन्ट विश्वविद्यालय में फ्लेमिश भाषा की प्रधानता हो गई।

स्केल्ट नदी के बायें किनारे के सम्बन्ध में हालैंड और बेल्जियम के बीच में झगड़ा चल रहा है। इस समय स्केल्ट नदी के दोनों किनारे डच लोगों के अधिकार में है। एष्टवर्प बन्दरगाह को सुरक्षित रखने के लिये बेल्जियन लोग बायें किनारे पर अपना अधिकार चाहते हैं।



२६—भूमध्यसागर में जातियों का संघर्ष

प्राचीन रोमन काल में भूमध्यसागर पहले पहल प्रसिद्ध हो गया । जब योरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका में घुसने लगीं तब भूमध्यसागर का महत्व और भी अधिक बढ़ गया । स्वेज़ नहर के खुल जाने से भूमध्य-सागर पहले से अधिक महत्वपूर्ण बन गया । यहाँ कई जातियों के हितों का संघर्ष होता है । फ्रांस के लिये फ्रांस से उत्तरी अफ्रीका को जाने वाले मार्ग बड़े काम के हैं । इटली भूमध्यसागर को एक रोमन भील समझता है । इटली से ट्रिपली और लालसागर पर बसे हुए इटैलियन उपनिवेशों और एबीसीनिया को मार्ग गये हैं । एड्रियाटिक सागर पर इटली का प्रायः निरंकुश अधिकार है । पश्चिम से पूर्व (भारतवर्ष) को जाने वाला समुद्री मार्ग ब्रिटेन के लिये जीवन-मरण का प्रश्न रखता है । जिब्राल्टर, माल्टा, साइप्रस और स्वेज़ इस जल-मार्ग की कुंजी हैं । ग्रीस (यूनान) को यह सख्त नहीं है कि रोडदीप और डोडेकनीज़ द्वीपों पर इटली का अधिकार जमा रहे । रूस के दक्षिणी तट के जलमार्ग बास्फोरस और डार्डनेल्स जलसंयोजकों में होकर पूर्वी भूमध्यसागर में पहुँचता है । इसलिये रूस चाहता है कि भूमध्यसागर में किसी एक जाति का विशेष रूप से प्रभुत्व न होने पावे ।

२७-पिछली लड़ाइयों में टर्की का हास

बाल्कन युद्ध के बाद यूरुपीय जातियों के ऊपर से टर्की का राज्य जाता रहा। बड़ी लड़ाई ने अरब, सिरिया, पेल्लेस्टाइन और इराक के अरबों को भी तुर्की शासन से मुक्त कर दिया। मिस्र देश से तुर्की का प्रभुत्व बड़ी लड़ाई के आरम्भ में ही जाता रहा था। इस समय टर्की में तुर्कों की प्रधानता है। केवल दजला और फरात नदियों के निकास के पास खुर्द लोग कुछ अल्प संख्या में रहते हैं। बड़ी लड़ाई के बाद सिरिया पर फ्रांस का मेंडेट होगया। पेल्लेस्टायन, ट्रान्स जार्डन और इराक पर ब्रिटिश मेंडेट हो गया। पीछे से इराक प्रायः स्वाधीन हो गया। अरब देश में मित्रराष्ट्रों ने अपने अपने पिछू कर्ई सरदार और अमीर खड़े कर दिये। अधिक दक्षिण की ओर इन्ससऊद ने बडुतों को जीत (या मिला) लिया।

बड़ी लड़ाई के बाद बास्फोरस और डार्डनेल्स के जलसंयोजकों के ऊपर से किजेबन्दी हटा ली गई थी। लेकिन १९३६ में इस प्रदेश पर टर्की ने फिर अपना पूरा अधिकार कर लिया।

२८—टर्की

टर्की को दस वर्षों में चार विकराल लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। १९११-१२ में ट्रिपली में इटली से तथा १९१२ में बाल्कन युद्ध हुआ। १९१४-१८ के योरोपीय युद्ध में टर्की ने जर्मनी का साथ दिया। १९२१-२२ में ग्रीस से टर्की को घोर युद्ध करना पड़ा। इसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा की अध्यक्षता में टर्की का देश शान्ति की ओर बढ़ने लगा। टर्की का राज्य योरोप में कुस्तन्तुनिया और उसके पड़ोस तक ही सीमित रह गया। एशिया में अनातोलिया का विशाल पठार है। कमालपाशा ने देश को उठाने के लिये रेल, सड़क और कारबार की ओर राष्ट्र का पूरा जोर लगा दिया। अनातोलिया पठार के आर पार जाने वाली एक ऐसी रेल की योजना हो रही है जो काला सागर पर बसे हुए समसौन बन्दरगाह को भूमध्यसागर के मर्सिना बन्दरगाह से मिलावेगी। एक लाइन अंगोरा से रूसी सीमा तक जावेगी। आजकल अंगोरा को अंकारा और कुस्तन्तुनिया को इस्तम्बोल कहते हैं।

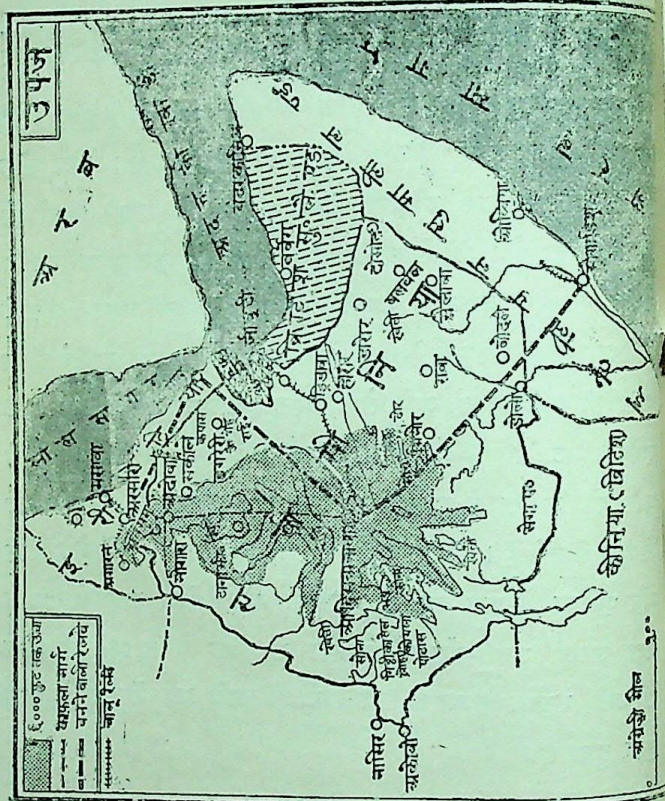
बड़ी लड़ाई के बाद रूस और टर्की में बड़ी मित्रता हो गई। हाल में टर्की के पुराने दुश्मन ग्रीस से भी मित्रता हो गई है।

२६—पश्चिमी एशिया में अंग्रेजी अंकुश

पूर्वी भूमध्यसागर को छूने वाला जो स्थल प्रदेश लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में स्थित है वह ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े काम का है। यहीं होकर हिन्दुस्तान और हिन्दमहासागर के लिये छोटा समुद्री रास्ता है। यहीं होकर हिन्दुस्तान और आस्ट्रेलिया के लिये ब्रिटिश हवाई जहाज़ जाते हैं। इसी मार्ग को काटने के लिये जर्मनी ने टर्की के द्वार पार जाने वाली बर्लिन-बग़दाद रेलवे की योजना की थी। फारस की खाड़ी से टर्की होकर योरोप जाने वाला स्थल मार्ग काफी लोकप्रिय हो गया है। इस मार्ग पर इस समय विशेष रूप से ब्रिटेन का नियन्त्रण है। इस मार्ग में बाधा न पड़े इसलिये मित्र देश को पूरी आज़ादी नहीं दी जा सकती। इसी से ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन्सऊद का ट्रान्सजार्डन तक बढ़ना सहन नहीं कर सकते। बड़ी लड़ाई ने इस प्रदेश पर से तुर्की शासन को उठा लिया। लेकिन एग्जीसीनिया की विजय और योमेन (यमन) में इटली की चालों से यह मार्ग संकट में पड़ता जा रहा है।

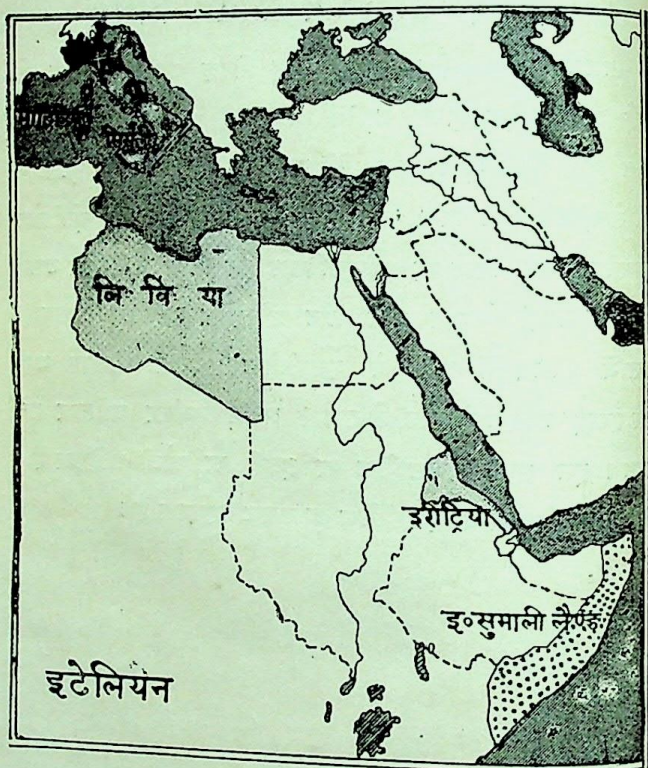
३०--फ्रांस और पश्चिमी भूमध्यसागर

जब से सिरिया के ऊपर फ्रांस का मेंडेट (शासन) हुआ है तब से पूर्वी भूमध्य सागर भी फ्रांस के काम का हो गया है। लेकिन फ्रांस का प्रधान साम्राज्य पश्चिमी भूमध्य सागर के उत्तरी किनारे से आरम्भ होता है। थोड़े से स्पैनिश जोन (पेटी) और ज़रा से अन्तराष्ट्रीय टैजिर को छोड़ कर सारा उत्तरी अफ्रीका (एटलस प्रदेश) फ्रांस के अधिकार में हैं। विषुवत रेखा के पास भूत पूर्व जर्मन उपनिवेशों पर फ्रांसीसी अधिकार हो जाने से फ्रांस का साम्राज्य भूमध्य सागर के दक्षिणी तट से ३००० मील दक्षिण को ओर बढ़ गया है। यहाँ से फ्रांस को शान्ति के समय कच्चा माल और लड़ाई के समय असंख्य सिपाही मिलते हैं। वैसे तो फ्रांस का राज्य अफ्रीका के पूर्व में मेडेगास्कर और एशिया के फ्रेंच इण्डोचीन पर भी है। लेकिन फ्रांस को सब से बड़ा लाभ उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका से होता है। इसी से फ्रांस पश्चिमी भूमध्य सागर के जल-मार्ग को अपने हाथ में रखने के लिये तुला हुआ है।



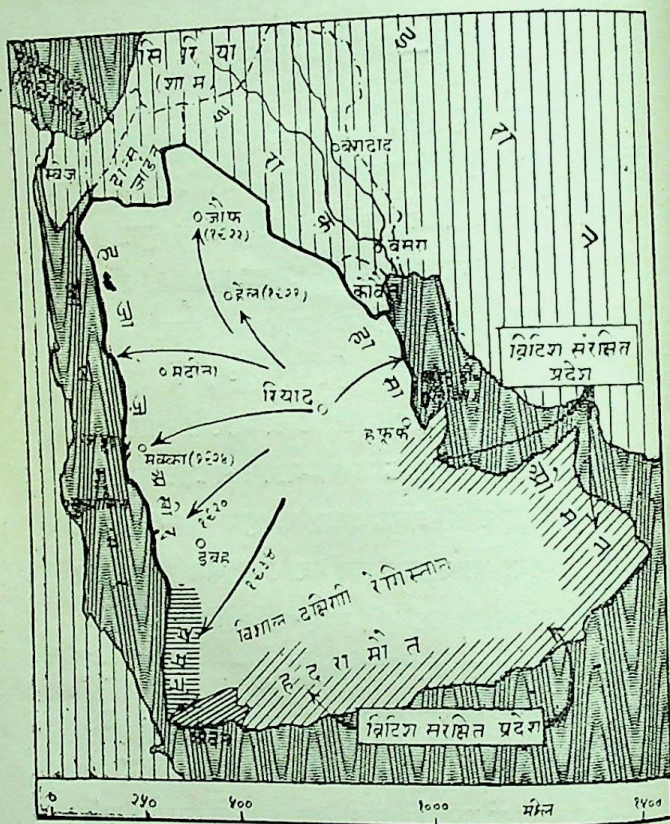
३१ इटली और लाल सागर

साम्राज्यवाद की दौड़ में इटली कुछ पिछड़ गया। अफ्रीका के अच्छे अच्छे प्रदेश दूसरी जातियों ने घेर लिये। भिन्न देश के पास मिला हुआ लिबिया का प्रायः रेगिस्तानी प्रदेश १९१२ में इटली ने टर्की से छीन लिया। लाल सागर के किनारे इरीट्रिया और इटैलियन सुमाली लैंड पर उसने पहले ही अधिकार कर लिया था। फिर उसने अदन की खाड़ी के पास वाले अरब प्रदेश पर अधिकार जमाया। अन्त में १९३५ में इटली ने एबीसीनिया पर धावा बोलकर बम्ब और हवाई जहाजों के जोर से वहाँ ६ महीने के भीतर अधिकार कर लिया। इस समय एबीसीनिया पर इटली का फौजी अधिकार है। इसी से इटली का राजा एबीसीनिया का सम्राट कहलाता है।



३२-एवीसीनिया

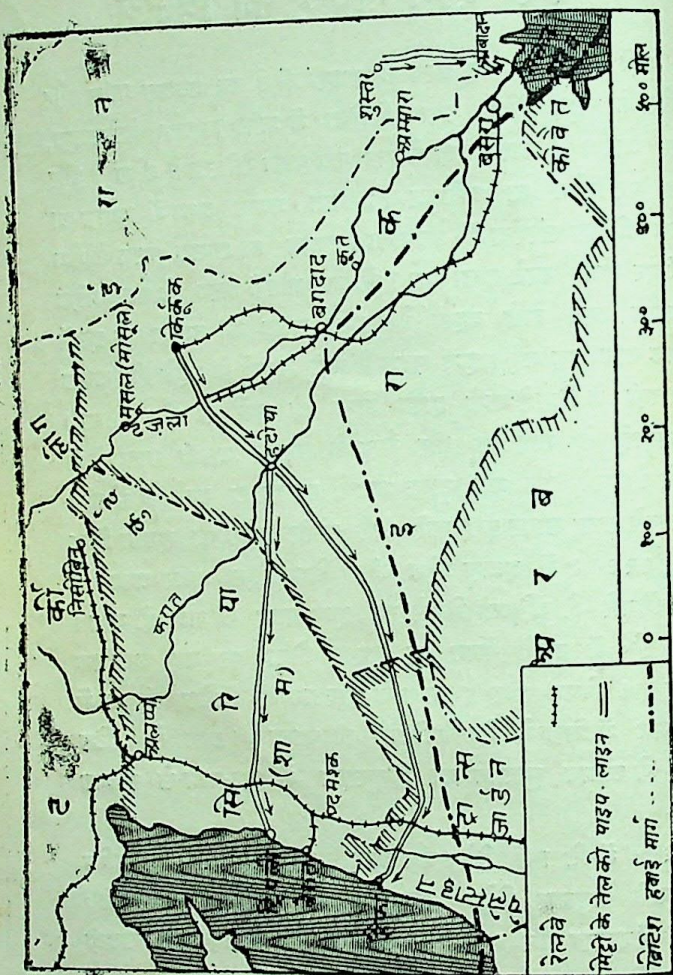
अब से ५० वर्ष पहले से ही इटली की आँख एवीसीनिया पर लगी थी। इटली ने पहले मसावा लिया और इरीट्रिया उप-निवेश की नींव डाली। फिर इटली ने (इटेलियन) सुमालीलैंड पर अधिकार घोषित किया। दस वर्ष के बाद इटली को फौज ने एवीसीनिया पर चढ़ाई की। लेकिन अदोवा की लड़ाई में इटली की बुरी तरह से हार हुई। हाल (१९३६ ई०) में इटली ने सुसज्जित होकर इरीट्रिया और सुमालीलैंड की ओर से एवीसीनिया पर फिर धावा बोला। उत्तरी फौज को अधिक सफलता मिली। आदिस अबाबा और उत्तरी प्रदेश इटली के हाथ आया। इटली का राजा एवीसीनिया का सम्राट बन गया। लेकिन गैस और हवाई जहाजों से दब जाने पर भी वीर एवीसीनियन लोगों ने आजादी की लड़ाई बराबर जारी रखी है। दुर्गम पहाड़ी भागों में इस समय भी इटली का अधिकार नहीं हो पाया है। वहाँ एवीसीनिया की ही सरकार मानी जाती है। एवीसीनिया के सम्राट हेल सलासी योरुप में निर्वासित हैं। लेकिन वे वहीं से अपने देश को आजाद करने में लगे हुए हैं।



३३—इब्न सऊद की विजय

बड़ी लड़ाई के बाद अरब के बाहरी प्रदेशों का बटवारा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हो गया। सिरिया में फ्रांस का और पेलोपेनेस, ट्रान्स जार्डन (जार्डन नदी के इस पार वाला रेगिस्तानी प्रदेश) और इराक़ पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। प्रधान अरब में हज़ाज़ का शासक ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। हज़ाज़ का शासक अरब के शेष भागों पर राज्य करने वाला था। लेकिन भीतरी अरब के नज्द प्रदेश पर राज्य करने वाले वहबी नेता इब्न सऊद के उत्थान से इसमें भयानक बाधा पड़ गई। इब्न सऊद ने बड़ी लड़ाई के पहले ही फारस की खाड़ी के किनारे वाले हासा प्रान्त को तुर्कों से छीन लिया। बड़ी लड़ाई के बाद हैल और जौफ़ के सरदार उसकी मातहत में आ गये। उसने एक बार ट्रान्स जार्डन पर हमला करने की सोची। फिर उसने लाल सागर के किनारे वाले असीर प्रदेश पर हमला किया और १९२४-२५ में हज़ाज़ प्रदेश जीत लिया। इस प्रकार अरब देश के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक इब्न सऊद का राज्य हो गया। १९३४ ई० में उसने यमन पर हमला किया। पर यह अभी तक स्वाधीन है। ओमन और हदरामौत के सुल्तान भी ब्रिटिश संरक्षण में हैं। ओमन में मिट्टी के तेल के मिलने की आशा है। इसी से ब्रिटिश शासकों ने ओमन सुल्तान का हिन्दुस्तान में धूम-धाम से स्वागत किया।

१९२७ में जिहा में ब्रिटेन और इब्न सऊद के बीच में एक सन्धि हुई। इसके अनुसार ब्रिटेन ने इब्न सऊद की स्वाधीनता मान ली। १९३२ में हज़ाज़ और नज्द के राज्य का नाम बदल कर सऊदी अरब रख दिया।

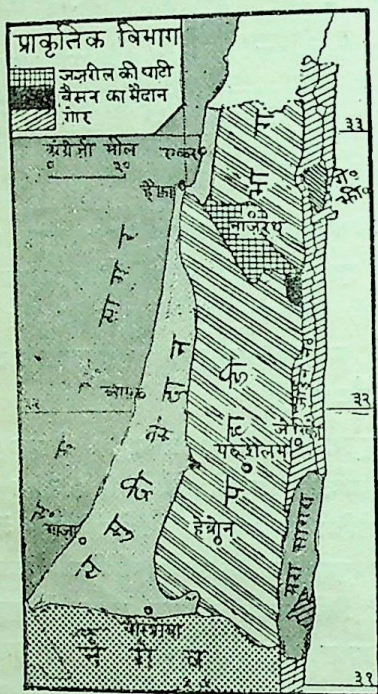


३४—इराक़ के मार्ग और मिट्टी का तेल

बड़ी लड़ाई के बाद इराक़ से तुर्की राज्य चला गया और उसके स्थान पर अंग्रेज़ी राज्य हो गया। १९३२ में ब्रिटिश मंडेट (सीधा शासन) भी समाप्त हो गया। ब्रिटेन की हवाई फ़ौजें और हवाई जहाज़ों के अड़े अब भी ज्यों के त्यों हैं।

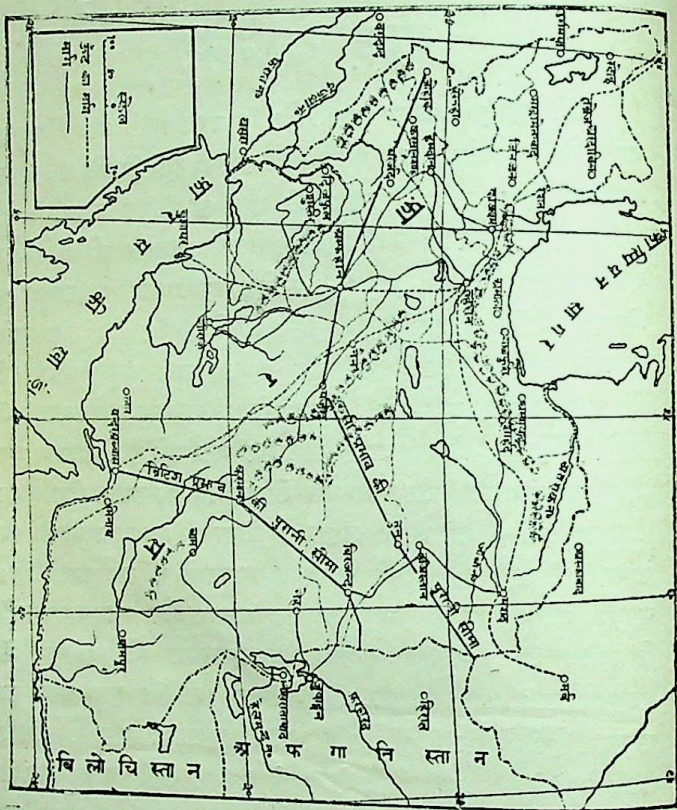
ब्रिटिश हवाई जहाज़ों का प्रधान मार्ग बग़दाद होकर हिन्दुस्तान को आता है। इससे बग़दाद में पुराने समय (जब केप आफ़ गुड-होप होकर समुद्री रास्ते का पता नहीं चला था और पश्चिमी एशिया के स्थल भागों का मेल बग़दाद में ही होता था) की महिमा फिर कुछ हद तक लौट आई।

इराक़ के मूसल प्रांत (मोसूल विलायत) में किरकूक के मिट्टी के तेल के चश्मे बहुत अच्छे हैं। इनको लेने के लिये फ़्रांस और टर्की ने भी कोशिश की। लेकिन इनका अधिकार ब्रिटेन के हाथ में ही रहा। फिर यहाँ के तेल का कुछ भाग फ़्रांस को भी मिलने लगा। इसी से इस तेल को लेने के लिये पाइप की एक लाइन किरकूक से सिरिया के ट्रिपोली बन्दरगाह तक जाती है। ब्रिटिश पाइप लाइन किरकूक से पेलेस्टाइन के हैफ़ा बन्दरगाह को जाती है।



३५— पेलेस्टाइन (फिलिस्तीन) के यहूदी उपनिवेश

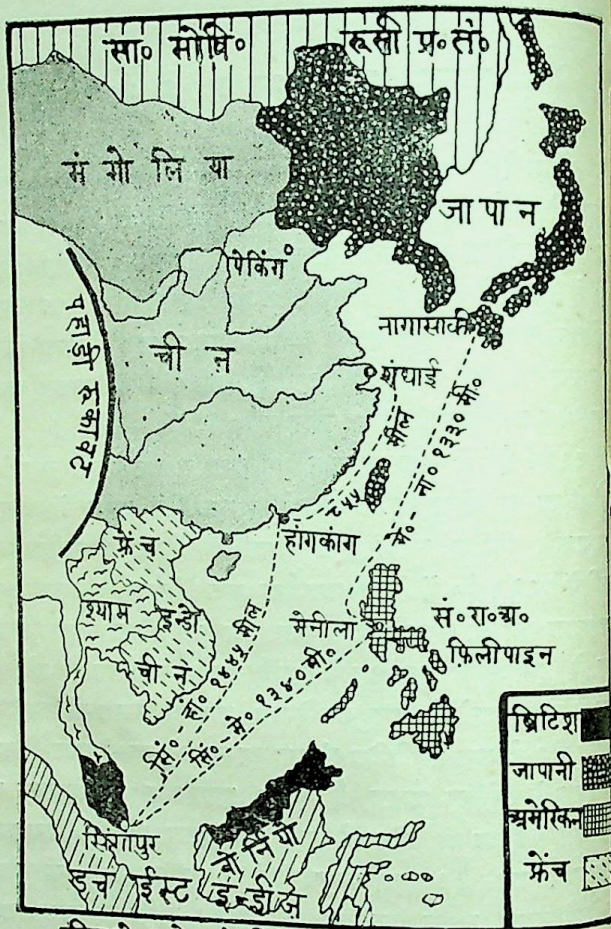
बड़ी लड़ाई के अक्सर पर ब्रिटेन ने यहूदियों से व्यापारिक लाभ उठाने के लिये पेलेस्टाइन में यहूदियों का राष्ट्रीय गृह (उपनिवेश) बनाने का वचन दिया। साथ ही साथ अरबी लोगों से सैनिक सहायता लेने और उन्हें शान्त रखने के लिये ब्रिटेन ने अरब प्रदेश को अविच्छिन्न रखने का वचन दिया। इन परस्पर विरोधी दोनों बातों को सम्भव कर दिखाना ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिये भी टेढ़ी खीर है। इस समय पेलेस्टाइन में ७३ फी सदी अरबी और १७ फी सदी यहूदी लोग रहते हैं। इन १७ फी सदी यहूदियों में आधे से अधिक यहूदी पेलेस्टाइन में ब्रिटिश मंडेट होने के बाद बाहर से आकर बस गये हैं। लगभग एक तिहाई यहूदी आबादी खेती के काम में लग गई है। ज़मीन दिलाने का काम यहूदियों की ज़िओनिस्ट संस्था ने किया है। यह यहूदियों की सरकारी संस्था है और उपनिवेश सम्बन्धी मामलों को तय करती है। यहूदी लोग अधिकतर समुद्र-तट पर जाफा और एका बन्दरगाहों के बीच में बसे हैं। कुछ हाफा-नाज़रथ के दक्षिण में एस्दरान घाटी और गेलिली झील के पास बसे हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि पेलेस्टाइन में ब्रिटिश साम्राज्य स्थायी रूप से बनाये रखने के लिये ही अरबी लोगों के पुराने दुश्मन यहाँ लाकर बसाये गये हैं। कुछ भी हो, अरबी लोग नये आने वाले यहूदी और ब्रिटिश-शासकों का घोर विरोध करते हैं। इस समय पेलेस्टाइन में एक प्रकार का फौजी शासन (मार्शल ला) है।



३६--ईरान का तेल और रेलमार्ग

फारस देश का आजकल सरकारी नाम ईरान हो गया है। बड़ी लड़ाई के पहले यह देश दो साम्राज्यों के प्रभुत्व में था। उत्तरी भाग में रूसी और दक्षिणी भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व था। इससे बहुत पहले १६०१ ई० में ब्रिटेन को ईरान में मिट्टी के तेल का पता लगाने का विस्तृत अधिकार मिल गया था। इसको उत्तरी सीमा तहरान के उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व को जाती थी। इसी से एंग्लो पर्शियन आयल कम्पनी नाम की अंग्रेजी कम्पनी की बुनियाद पड़ी।

१६३२ ई० में रिज़ाशाह पहलवी की प्रबल सरकार ने इस कम्पनी के पट्टे को रद्द कर दिया। इससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक जगत में तहलका मच गया। ब्रिटिश सरकार इस कम्पनी के हिस्सों की मालिक थी। इसलिये १६३३ ई० में फिर से समझौता हुआ। तेल का पता लगाने का क्षेत्र आधा कम कर दिया गया। कुछ और भी परिवर्तन हुये। रिज़ाशाह ने इम्पोरियल एअरवेज़ के हवाई जहाज़ों को ईरान के प्रदेश के ऊपर से होकर उड़ने से मना कर दिया। साथ ही फारस की खाड़ी के बेहरिन द्वीप के ऊपर से ब्रिटिश संरक्षण दूर करवाने का भी प्रयत्न हो रहा है। ईरान में रेलों का अभाव है। रूस, इराक और बलोचिस्तान की रेलवे लाइनें ईरान की सीमा के पास तक (तब्रेज़, कस्शीरीं, दज़दाब) आकर ठहर जाती हैं। फारस की खाड़ी से पाइप लाइन के पास-पास एक रेलवे लाइन शूस्तर तक गई है। इसको कास्पियन सागर तक ले जाने का विचार हो रहा है।



चीन के पड़ोस में विदेशी पूर्वी राज्य

३७-चीन के पड़ोस में विदेशी शक्तियों का जमघट

अगर चीन का देश योरुप से अधिक दूर न होता तो भारतवर्ष की तरह चीन भी बहुत पहले ही अपनी आजादी खो बैठता। जब धुआँकश जहाज (स्टीमर) तेजो से चलने लगे तब योरुपीय शक्तियाँ धीरे धीरे चीन में घुसने का प्रयत्न करने लगीं। चीन में समुद्रीय रास्ते से ही आसानी से घुसना हो सकता है। पश्चिम की ओर ऊँचे पहाड़ चीन को एशिया के दूसरे भागों से अलग करते हैं। उत्तर की ओर से रूस का प्रभाव पड़ता है। अतः योरुपीय शक्तियाँ उन्नीसवीं सदी के अन्त में और बीसवीं सदी के आरम्भ में जलमार्गों द्वारा चीन में प्रवेश करने लगीं। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये चीन में स्वतन्त्र सन्धि-सम्बन्धी बन्दरगाह (Treaty Ports) स्थापित किये।

जापान ने कोरिया और मंचूकुओ (मंचूरिया) में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब वह उत्तरी चीन में बढ़ रहा है। ब्रिटन ने हांगकांग पर अधिकार करके कैंटन और दक्षिणी चीन के व्यापार को अपनाया। सिंगापुर का ब्रिटिश जहाजी अड्डा चीन से केवल १५०० मील दूर है। इंडोचीन में फ्रांस का अधिकार है। संयुक्तराष्ट्र अमरीका फिलीपाइन द्वीप में डटा हुआ है। मंचूरिया में जापानी अधिकार हो जाने के कारण रूस का चीन से सीधा सम्बन्ध नहीं रह सका है। डच लोग अधिक दक्षिण की ओर पड़ गये हैं। वे अधिक बलवान भी नहीं हैं।

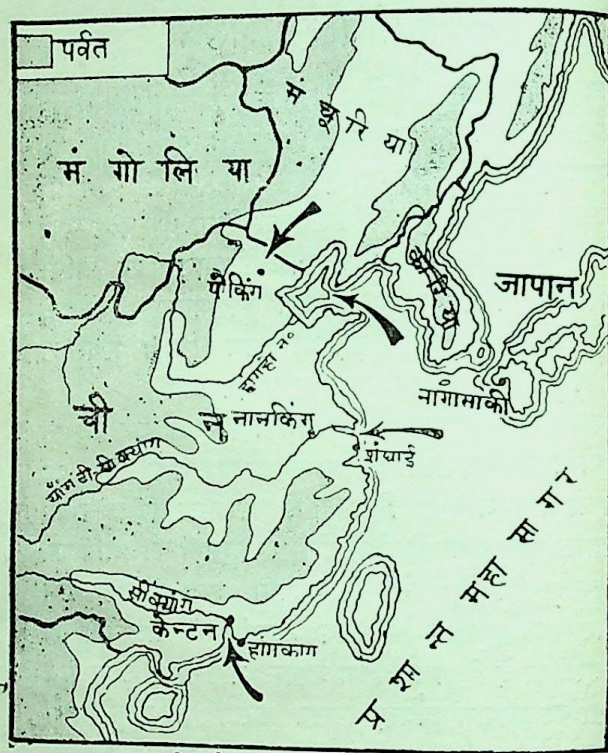


जापानी साम्राज्य

३८-जापानी साम्राज्य

जापान ने योरुपीय शक्तियों की तरह नये हथियारों से सुसज्जित होकर हाल में फैलने का प्रयत्न किया है। पर आगे बढ़ने का काम मजबूती के साथ हो रहा है। १८९४-९५ में चीन को हरा कर उसने फारमूसा पर अधिकार कर लिया। १९०४-५ में रूस को हरा कर जापान ने कोरिया और पोर्टआर्थर पर अधिकार कर लिया। १९१० में कोरिया देश खुल्लमखुल्ला जापानी साम्राज्य में मिला लिया गया। साथ ही साथ दक्षिणी मंचूरिया जापान अपनी स्थिति को मजबूत करता गया।

बड़ी लड़ाई में क्याओचाओ से जर्मनों को भगा कर जापान ने अपना अधिकार कर लिया। बड़ी लड़ाई के समाप्त होने पर क्याओचाओ नाम मात्र के लिये चीन को लौटा दिया गया, लेकिन प्रशान्त महासागर के जिन द्वीपों पर जर्मनी का अधिकार था, उन पर राष्ट्र-संघ की ओर से जापान राज्य करने लगा। मंचूरिया पर हमला करने के समय राष्ट्रसंघ की सदस्यता से जापान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रशान्त महासागर के भूतपूर्व जर्मन प्रदेशों पर जापान पूर्ववत् शासन करता है। मंचूरिया में प्रचल हो जाने के बाद जापान ने उत्तरी चीन को अपनाने का निश्चय किया।

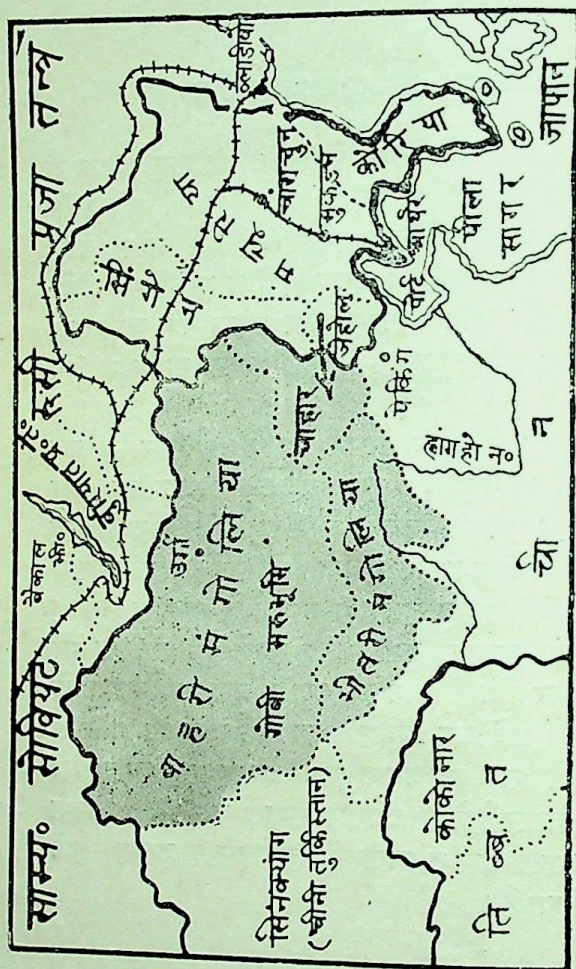


चीन में घुसने के मार्ग

३६—चीन में घुसने के मार्ग

बाहर से चीन में प्रवेश करने के लिये तीन प्रधान जल-मार्ग वहाँ की नदियों ने बनाये हैं। ह्वांगहो उत्तर चीन में, यांगटिसी-क्यांग मध्यचीन में और सीक्यांग दक्षिणी चीन में प्रवेश करने के लिये प्रधान मार्ग बनाती हैं। इन नदियों के मुहानों पर विदेशियों का अड्डा है। हांगकांग द्वीप और पड़ोस की जमीन पर अंग्रेजी अधिकार होने के कारण दक्षिणी प्रवेश मार्ग की कुंजी ब्रिटेन के हाथ में है।

यांगटिसीक्यांग के मुहाने पर बसे हुए शंघाई शहर में कई विदेशी शक्तियों का अड्डा है। इनमें संयुक्त-राष्ट्र अमरीका और ब्रिटेन प्रधान हैं। यांगटिसीक्यांग में सैकड़ों मील तक जहाज चल सकते हैं। लेकिन इसका मुहाना विदेशियों के अधिकार में होने के कारण विदेशी शत्रु इस नदी के मार्ग से लड़ाका जहाज भेज कर चीन के हृदय में छूरी भोंक सकते हैं। कोरिया पर जापानी अधिकार होने से चीन का उत्तरी जल-मार्ग जापान के अधिकार में है। सर्वोत्तम सुगम स्थल मार्ग उत्तर की ओर से है। यहाँ पहले रूस का प्रभाव था। आजकल मंचूरिया में जापान का अधिकार होने से उत्तरी स्थलमार्ग की कुंजी जापान के हाथ में है। इसी ओर से जापान ने चीन पर आक्रमण करने का निश्चय किया है।



मंगोल लोगों का प्रदेश

४०—मंगोल लोगों का देश

रूसी-जापानी लड़ाई के बाद जापान ने रूस और चीन के बीच वाले प्रदेश में बढ़ने की जी-तोड़ कोशिश की है। मंचूरिया पर अधिकार करने के बाद जापान ने रूस और चीन के बीच में नई स्थलीय रुकावट डाल दी है। इससे इन दोनों के बीच में स्थल-मार्ग द्वारा आसानी से आना जाना नहीं हो सकता। मंचूरिया में जापान का फौजी अड्डा स्थापित हो जाने से उसे उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर आक्रमण करने का अवसर मिल गया है।

जापानी सिपाही और एजेन्ट बड़ी तेजी से हाल में भीतरी (Inner) मंगोलिया में बढ़ रहे हैं। मंचूकुओ के सिंगन प्रान्त में रहने वाले २० लाख मंगोल लोग उसके शासन में पहले से ही आ गये हैं। बचे हुए ३० लाख मंगोलों में से १० लाख बाहरी (Outer) मंगोलिया के रेगिस्तान में, १० लाख भीतरी मंगोलिया में और १० लाख चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत के कोको-नार प्रान्त और एशियाई रूस के वुरियत प्रजातन्त्र में रहते हैं।

४१-मंचूकुओ और रूस-जापान

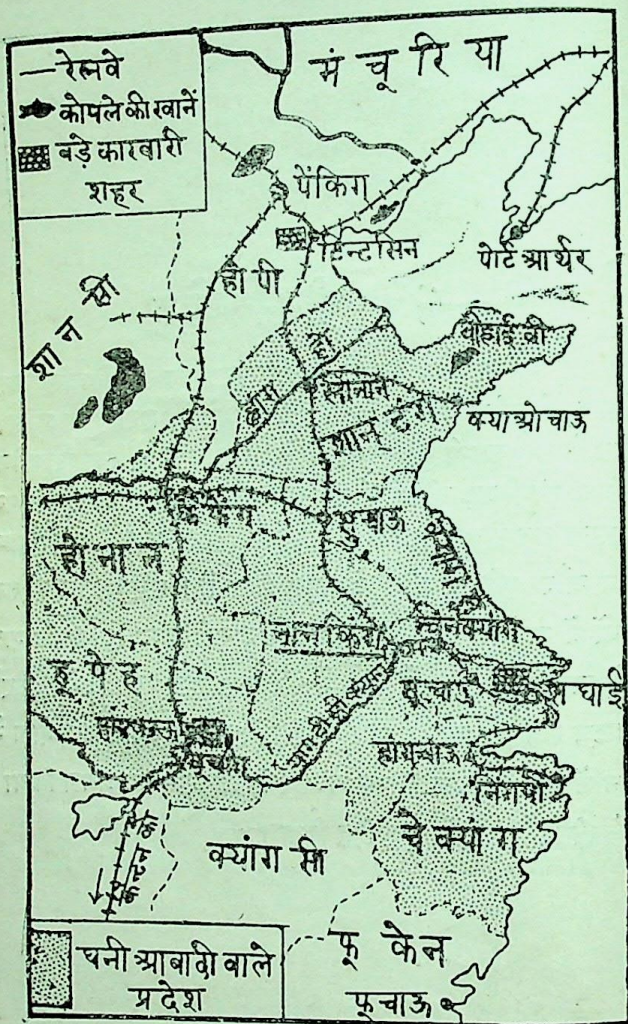
जापान ने मन्चूरिया को चीन से छीन कर पहले ही मंचू-कुओ नाम से एक अलग राज्य स्थापित कर लिया । मन्चूरिया (मंचूकुओ) पर जापानी अधिकार हो जाने से रूस, साइबेरिया और प्रशान्त महासागर तट (व्लाडी वोस्टक) के बीच में आने जाने के मार्गों में बाधा पड़ती है । ट्रान्स साइबेरियन रेलवे का मार्ग अमूर नदी के उत्तर में है । १८९६ में 'जार की सरकार ने चीन से सन्धि कर के व्लाडी वोस्टक तक उत्तरी मंचूरिया में होकर चाइनीज ईस्टर्न रेलवे निकाल ली । क्रांति के बाद रूस ने मंचूरिया के सब अधिकार छोड़ दिये । लेकिन इस रेलवे पर अपना अधिकार बना रक्खा । अन्त में रूस ने इस रेलवे के भी सब अधिकार जापान (मंचूकुओ) के हाथ बेच दिये । इन दो प्रधान रेलवे लाइनों के अतिरिक्त जापान ने मंचूकुओ में कई नई लाइनें निकाल कर मंचूरिया (मंचूकुओ) में रेलों का जाल सा बना लिया है ।



चीन विच्छेद

४२-चीन-विच्छेद

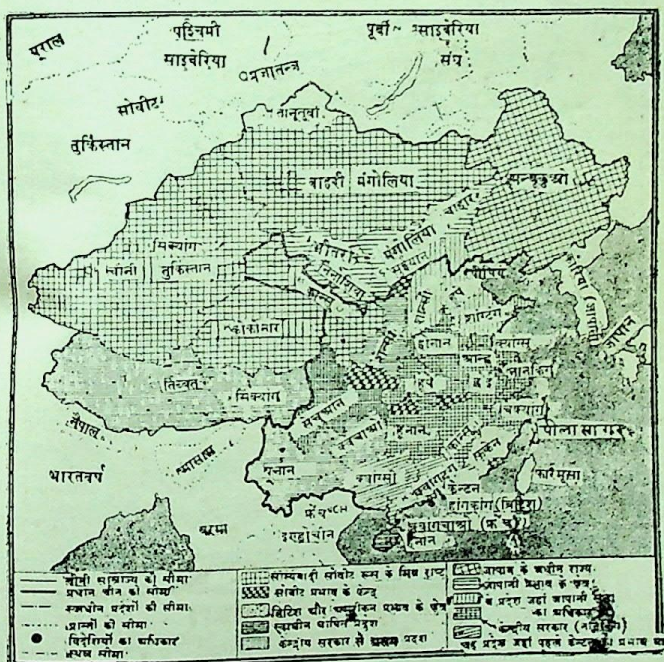
गत ९० वर्षों से चीन के प्राचीन साम्राज्य का विध्वंस करने में कई योरुपीय शक्तियाँ लग गईं । ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने चीन के कई बाहरी भाग दबा लिये । जापान ने कोरिया को छीनने के बाद मंचूरिया, भीतरी मंगोलिया और उत्तरी चीन को हड़पना आरम्भ कर दिया । नानकिंग की चीनी सरकार का प्रभुत्व मध्य चीन और दक्षिणी चीन में बहुत प्रबल है । पश्चिम के भीतरी भागों में मजदूरों और किसानों का पंचायती राज्य है । इनके शत्रु इन्हें अक्सर डाकू कहते हैं । वे फौजी शासकों का विरोध करते हैं । इन सय को एकता के सूत्र में बाँध कर चियांग-काई-शेक ने चीन में एक प्रबल प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया । इतने ही में जापान ने युद्ध छेड़ दिया ।

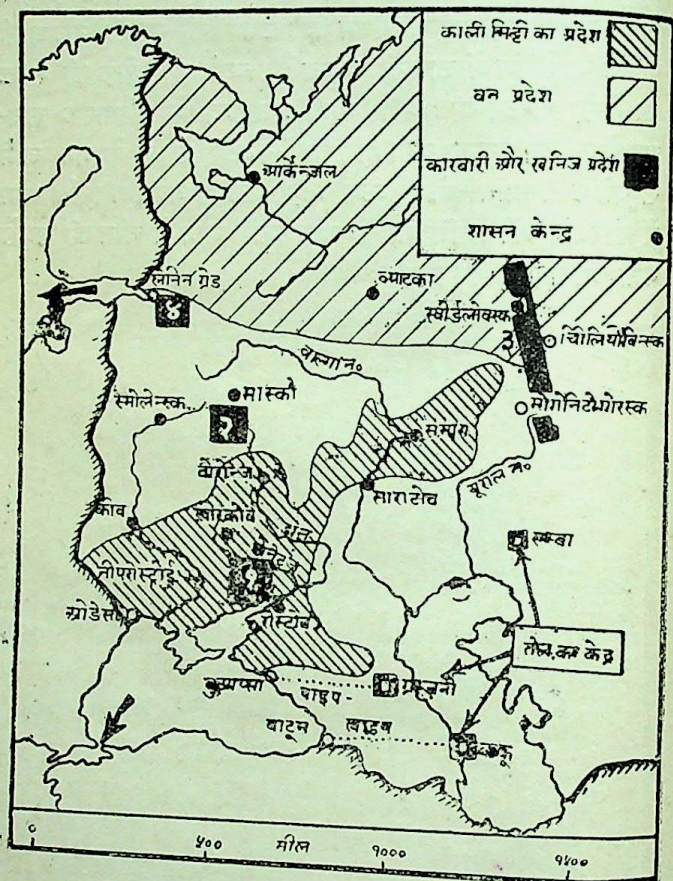


नानकिंग की सरकार

४३-नानकिंग की सरकार

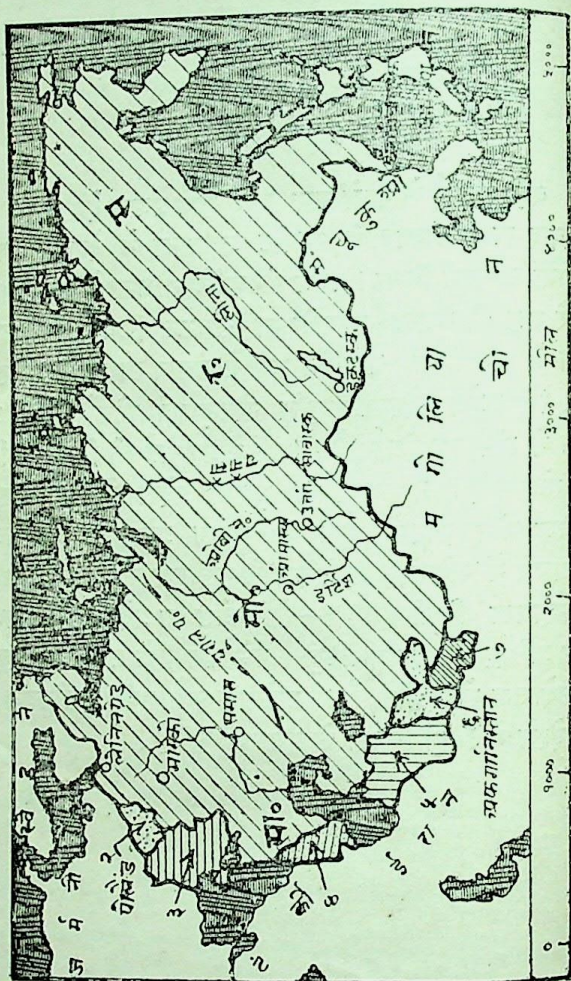
नानकिंग की सरकार च्यांग काई शेक की अध्यक्षता में मध्य चीन के उन प्रान्तों पर राज्य करती है जो यांग्तिसीक्यांग के उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं। उत्तर की पुरानी राजधानी पेकिंग या पेपिंग में जापानी प्रभुत्व है। च्यांग काई शेक की शक्ति का केन्द्र कैन्टन था। यहीं चीनी प्रजातन्त्र के संस्थापक सन-यातसेन का प्रभुत्व था। हांगकाओ-कैन्टन रेलवे के बन जाने से यांग्तिसीक्यांग और कैन्टन प्रदेश एक हो गये हैं। इसी भाग में कारवार की अधिकता है और इसी भाग में चीन की सबसे घनी आबादी बसी हुई है।





४४—नवीन रूस

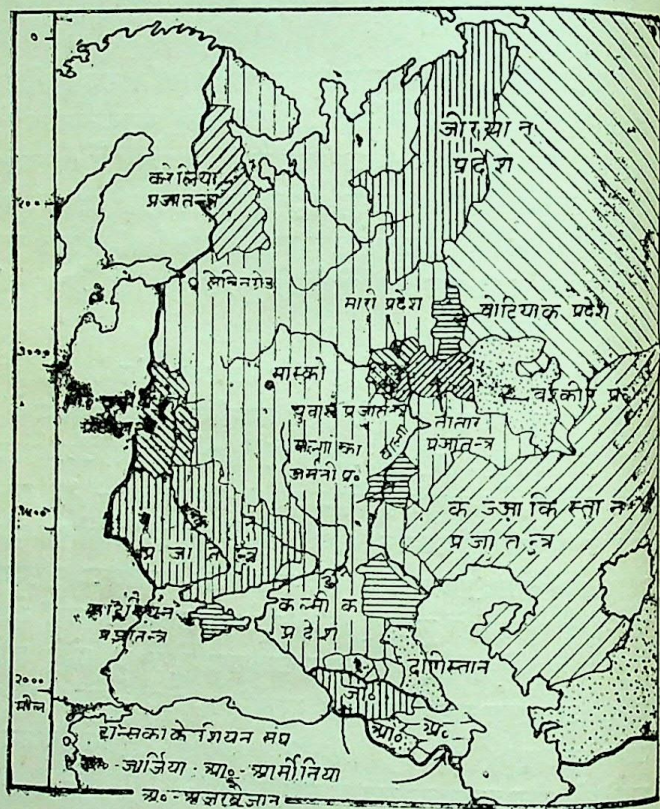
बड़ी लड़ाई के पहले रूस एक कृषि-प्रधान देश था। क्रान्ति के बाद रूसी साम्यवादी सोविएट प्रजातन्त्र ने देश में कारवार बढ़ाना आरम्भ किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने बड़े पैमाने पर सारे राष्ट्र को समस्त सम्पत्ति का संगठन किया और उसे एक सूत्र में बांध दिया। योरोपीय रूस में प्रधान कारवारी प्रदेश चार हैं। १—यूक्रेन प्रदेश की वृद्धि डोनेट्ज़ के कोयले और क्रोवोई रोग के लोहे पर निर्भर है। यहीं नीप्रोस्ट्रोई की विशाल विजली का स्टेशन है। २—मध्यवर्ती मास्को प्रदेश में कई प्रकार के खनिज और कारवार हैं। ३—यूराल प्रदेश की खनिज को निकालने में पश्चिमी साइबेरिया के कुस्नेट्ज़ की कोयले की खानों से सहायता मिली है। ४—लेनिनग्रेड का प्रदेश भी कारवार के लिये प्रसिद्ध है। काली मिट्टी (कर्नोज़म) के प्रदेश में रूस भर में सर्वोत्तम खेती होती है। काकेशस पर्वत और कास्पियन सागर के पड़ास में मिट्टी के तेल के प्रधान केन्द्र हैं।



४५-नवीन रूस के राजनैतिक विभाग

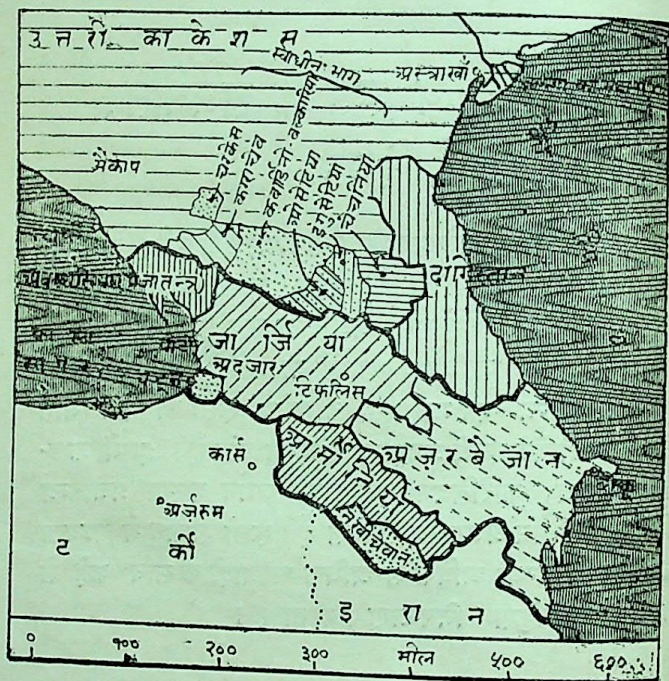
नवीन रूस को अल्पसंख्यक जातियों की सबसे विकट समस्याओं को हल करना पड़ा। १९२६ की मनुष्य-गणना के अनुसार रूस में १७४ भिन्न भिन्न जातियाँ रहती हैं। समस्त जन-संख्या लगभग १७ करोड़ है, जो हमारे देश की लगभग आधी है। इनमें $\frac{2}{3}$ लोग योरोपीय रूस में रहते हैं। एशियाई रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। दोनों ही भागों में कई प्रकार की प्राकृतिक सम्पत्ति है।

वर्तमान साम्यवादी सोवियट रूसी प्रजातन्त्र संघ में सात बड़े बड़े प्रजातन्त्र और कई छोटे छोटे स्वाधीन (घरेलू प्रबन्ध में) जिले शामिल हैं। बड़े बड़े प्रजातन्त्रों में कई छोटे छोटे प्रजातन्त्र राष्ट्र शामिल हैं। सात बड़े-बड़े प्रजातन्त्र राष्ट्र ये हैं :—(१) रूसी सोवियट साम्यवादी प्रजातन्त्र संघ। इसमें अधिकांश योरोप और पूरा साइबेरिया शामिल है। (२) श्वेत रूसी प्रजातन्त्र पश्चिमी योरोप की सीमा को छूता है। (३) यूक्रेन प्रजातन्त्र। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। (४) ट्रांस काकेशस प्रदेश के छोटे छोटे पहाड़ी प्रजातन्त्र राष्ट्र (जार्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान)। (५) ताजिकिस्तान। (६) युजबेकिस्तान, और (७) तुर्कमानिस्तान। आखिरी तीन प्रजातन्त्र सब के सब एशिया में स्थित हैं।



४६—योरुपीय रूस के राजनैतिक विभाग

रूस के तीन बड़े बड़े प्रजातन्त्र राष्ट्र पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी सीमा के पास स्थित हैं। श्वेत (हाइट) रूसी प्रजातन्त्र यूक्रेन और ट्रान्स काकेशस प्रजातन्त्र संघ। ट्रान्स काकेशस प्रजातन्त्र संघ में जार्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान के पहाड़ी प्रजातन्त्र शामिल हैं। योरुपीय रूस का शेष भाग साम्यवादी सोवेट रूसी प्रजातन्त्र संघ का अंग है। इसमें काइ-मिया प्रजातन्त्र, कारेलियन प्रजातन्त्र, जर्मन वात्गा प्रजातन्त्र आदि कई स्वाधीन प्रजातन्त्र शामिल हैं। रूसी शासन में सभ्यता और विद्या सम्बन्धी अधिक से अधिक आजादी के साथ कड़े से कड़ा आर्थिक अंकुश (नियन्त्रण) रहता है।



४७-काकेशस प्रदेश

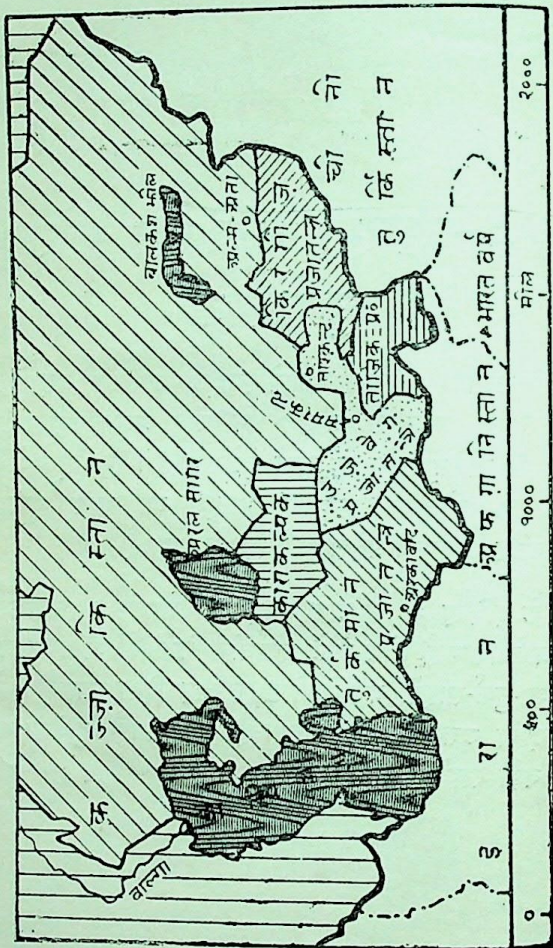
काकेशस प्रदेश कास्पियन सागर और काले सागर के बीच में स्थित है। मिट्टी के तेल की अधिकता होने के कारण इस प्रदेश का महत्व बहुत बढ़ गया है। १९१७ की क्रान्ति के बाद यहाँ १९२१ ई० तक गृह कलह चलती रही। इसके बाद रूसी प्रजातन्त्र सरकार ने यहाँ कई स्वाधीन प्रजातन्त्र स्थापित करके यहाँ के लोगों की राजनैतिक माँगें पूरी कीं।

(१) काकेशस प्रदेश के उत्तरी भाग में रूसी साम्यवादी सोवियट प्रजातन्त्र संघ का शासन है। इसमें कई छोटे छोटे स्वाधीन जिले शामिल हैं। (२) कास्पियन सागर के पश्चिमी किनारे पर दागिस्तान का प्रजातन्त्र है। (३) ट्रान्स काकेशस प्रजातन्त्र-संघ में जार्जिया (जिसकी राजधानी टिफलिस है), आर्मेनिया (राजधानी एरीवान) और अज़रबैजान (राजधानी बाकू) शामिल हैं। इन तीनों प्रजातन्त्रों में भी एक दो स्वाधीन जिले शामिल हैं।

४८—पश्चिमी साइबेरिया और तुर्किस्तान

रूसी सरकार पश्चिमी साइबेरिया के कारवार बढ़ाने और उसे योरोपीय भाग से जोड़ने का धोर प्रयत्न कर रही है। कुस्नेट्ज में, डोनेट्ज से छः गुना कोयला है। कुस्नेट्ज में ४५० बिलियन टन कोयला अन्दाजा गया है। यह भाग यूराल के खनिज और कारवारी प्रदेश से जोड़ा जा रहा है।

इसके दक्षिण में तुर्किस्तान है, जो आजकल कजाकस्तान प्रजातन्त्र और कई छोटे छोटे स्वाधीन जिलों में बँटा हुआ है। यह प्रदेश तुर्क-साइबेरियन रेलवे द्वारा जोड़ दिया गया है। रेलवे ताशकन्द से उत्तर की ओर बढ़ती है। यह लाइन दुनिया भर में सब से बड़ी रेलवे लाइन है।



४६—रूसी मध्य एशिया की जातियाँ

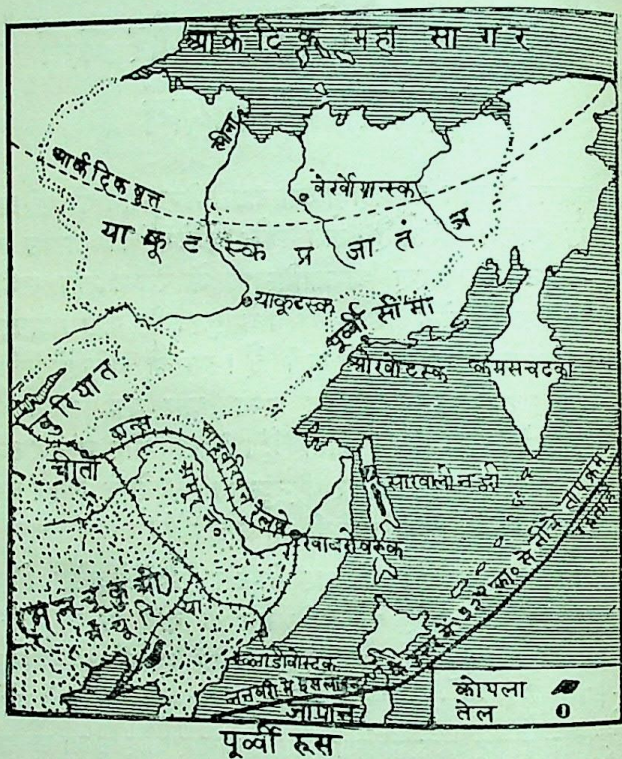
उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में तुर्किस्तान रूसी साम्राज्य में मिला लिया गया। ज़ार का साम्राज्य अफ़ग़ानिस्तान को छूने लगा। ज़ार की इस बढ़ती हुई शक्ति और ब्रिटिश भारत पर भावी आक्रमण को रोकने के लिये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। क्रान्ति के बाद इस प्रदेश में जो गृह-कलह फैली वह १९२४ तक शान्त न हुई। इस समय यहाँ निम्न राज-नैतिक विभाग हैं :—

कज़ाक़स्तान प्रजातन्त्र राज्य में अधिकतर घुमक्कड़ किरगीज़ लोग रहते हैं। काराकल्पक का प्रदेश स्वाधीन है। तुर्क़मानिस्तान में तुर्क़मान मुसलमान रहते हैं। उज़बेकिस्तान में कपास ख़ूब होती है। यहीं इस प्रदेश में सब से अधिक आबादी है। यहीं मध्य एशिया के तीन प्रधान नगर (ताशक़न्द, समरक़न्द और बुख़ारा) स्थित हैं। ताजकिस्तान पहाड़ी प्रदेश है। इसके पूर्वी भाग में ऊँचा पठार या दुनिया की छत है। किरगीज़िया में ढोर पालने वाले लोग रहते हैं।

५०—अफगानिस्तान और मध्य एशिया की सीमायें

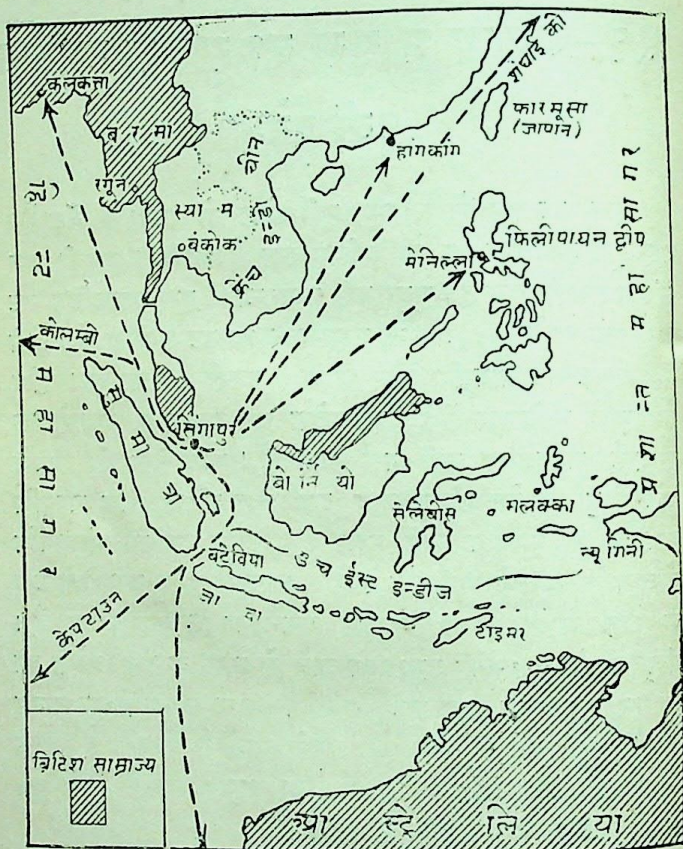
अफगानिस्तान का पहाड़ी देश उत्तरी हिन्दुस्तान को एशियाई रूस से अलग करता है। रूस और ब्रिटेन की आपस की पुरानी फूट के कारण अफगानिस्तान में रेल न खुल सकी। लेकिन रूस की रेलें (मर्ग के आगे कुश्क के पास) अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा को छूती हैं। इस की दक्षिणी सीमा के पास उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त और बलोचिस्तान की रेलवे लाइनें आकर रुक जाती हैं। हिरात और कन्धार तथा पेशावर और काबुल होकर हिन्दुस्तान की रेलवे लाइनें बड़ी आसानी से रूसी रेलों से जोड़ी जा सकती हैं।

अफगानिस्तान में कई बार ब्रिटिश फौजों ने प्रवेश किया १९११ में ब्रिटेन और अफगानिस्तान के बीच में नई सन्धि हुई। इस के अनुसार अफगानिस्तान की स्वाधीनता स्वीकार कर ली गई। रूस के विशेष अधिकार कुछ कम कर दिये गये। हिन्दुस्तान होकर अफगानिस्तान को हथियार और फौजी सामान मगाने की सुविधा कर दी गई।



५१—एशिया में रूस का सब से अधिक पूर्वी प्रदेश

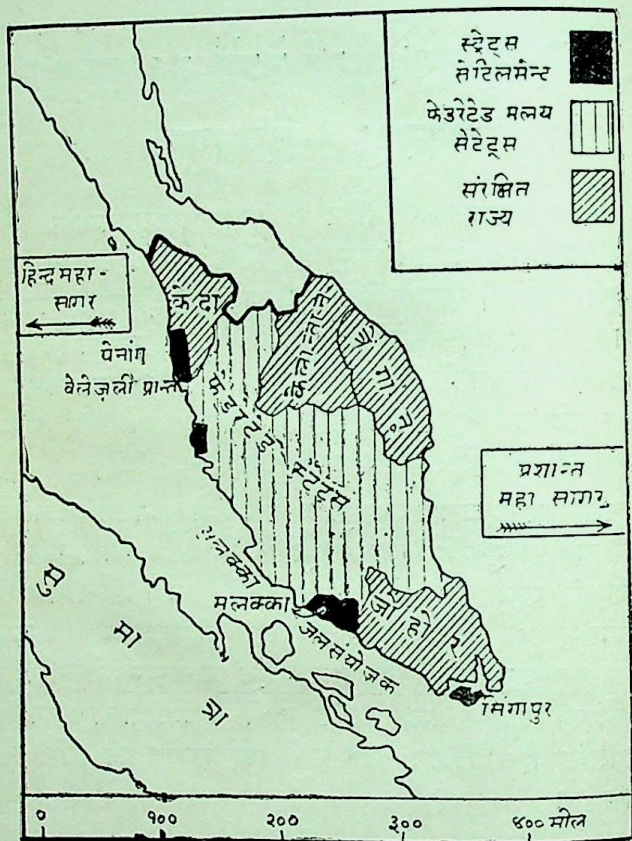
रूस का सब से अधिक पूर्वी प्रदेश दो भागों में बँटा है। याकुट्स्क प्रजातन्त्र सब से अधिक बड़ा है। लेकिन इसकी जन संख्या सब से कम है। सुदूर पूर्वी प्रजातन्त्र में कुछ आर्कटिक तट और समूचा रूसी प्रशान्त महासागर का तट शामिल है। इसी में कमचटका प्रायद्वीप और आधा (उत्तरी) साखालिन द्वीप जापान के अधिकार में है। इस प्रदेश की राजधानी खवारोव्स्क नगर है जो अमूर नदी पर स्थित है। साखालिन के कोयले और मिट्टी के तेल को छोड़कर इस प्रदेश की प्राकृतिक सम्पत्ति का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन अगली पंचवर्षीय योजना में रूस ने यहाँ कई रेलवे, कारखाने और व्लाडीवोस्टक के उत्तर में एक बड़ा बन्दरगाह बनाने का निश्चय किया है। मंचूरिया में जापानी प्रभुत्व हो जाने से रूस के इस प्रदेश को जापान का सदा भय लगा रहता है। इस समय केवल ट्रान्स साइबेरियन रेलवे इस भाग को दूसरे भागों से जोड़ती है। इसी से रूसी हवाई जहाजों का एक बड़ा अड्डा अचानक हमले को रोकने के लिये बनाया गया है।



५२--दक्षिणी-पूर्वी देशों का समुद्री चौराहा—सिंगापुर

विशाल प्रशान्त महासागर का पूर्वी दरवाजा पनामा और और पश्चिमी दरवाजा सिंगापुर है। सिंगापुर में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी भागों की रक्षा के लिये सबसे बड़ा जहाजी अड्डा बनाया गया है। जब १८१९ में रेफिल्स साहब ने सिंगापुर को मिलाया तो उन्होंने लिखा कि सिंगापुर के मिलाने से ब्रिटिश साम्राज्य को न केवल एक द्वीप मिला वरन् चीन-जापान और स्याम, कम्बोडिया के लिये जलमार्ग का अधिकार मिल गया।

सिंगापुर के जहाजी अड्डे के बनाने में लगभग १५ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस अड्डे से न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया की रक्षा करने में सुविधा होगी। यहाँ से चीन और जापान में भी ब्रिटिश हितों की रक्षा की जा सकती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इस अड्डे के सम्बन्ध में पूर्वी द्वीप समूहों की रक्षा के लिये हालैंड वालों ने ब्रिटिश से समझौता कर लिया है। लेकिन जापान इसको सन्देह की दृष्टि से देखता है।



५३—मलय प्रायद्वीप

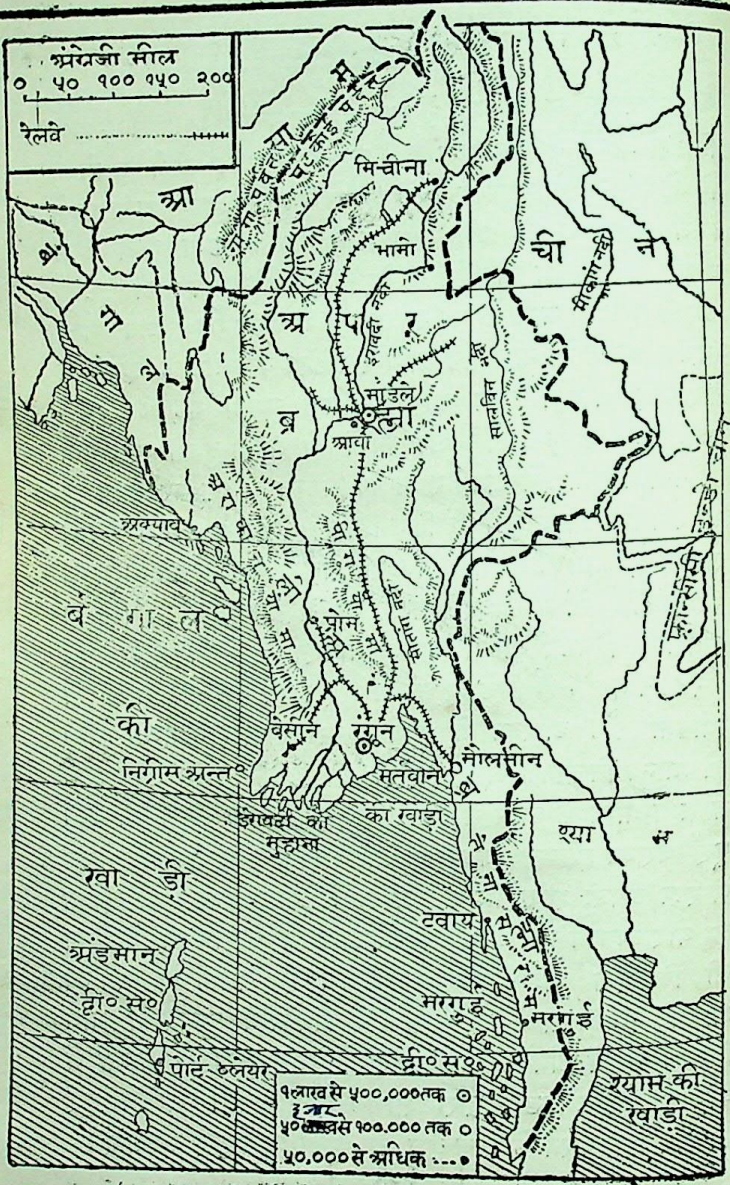
हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच में मलय प्रायद्वीप की स्थिति बड़े मार्के की है। अठारहवीं सदी के प्रायः अन्त में ईस्टइंडिया कम्पनी ने पेनांग में अपना अड्डा जमाया। मलका पर पहले पुर्चगालियों का अधिकार था। फिर डच (हालैंड) के लोगों ने यहाँ अपना अधिकार जमाया। अन्त में उनसे अँग्रेजों ने इसे छीन लिया। इसके बाद अँग्रेजों ने सिंगापुर में अपना उपनिवेश बनाया। इस समय समस्त मलय प्रदेश पर ब्रिटिश अधिकार है। पेनांग वेल्लेजली प्रान्त मलका और सिंगापुर में ब्रिटिश काउन कलोनी (स्ट्रैट्स सेटिलमेन्ट) हैं। चार फेडरेटेड मेले स्टेट्स (रियासतों में) ब्रिटिश प्रभुत्व है। नाम मात्र के लिये इन रियासतों में अलग अलग सुलतान हैं। मलय प्रायद्वीप के दूसरे (केडा, केलन्तान, ट्रेंगानू और जोहोर राज्यों के शासक अलग अलग हैं। वे ब्रिटिश संरक्षता में हैं और अँग्रेजी सलाहकारों के अनुसार चलते हैं।

अब से ६० वर्ष पहले यहाँ टिन की खानों का पता चला तभी से अँग्रेजों ने इस प्रायद्वीप के भीतरी भागों में घुसना शुरू किया आज कल रबर और टीन यहाँ की प्रधान सम्पत्ति है। रबर के वगैरों में हिन्दुस्तानी और टीन की खानों में चीनी मजदूर काम करते हैं। इस समय हिन्दुस्तानी और चीनी लोगों की संख्या मिलकर यहाँ के मूल निवासी मलय लोगों से भी अधिक है।

५४-भारतवर्ष

भारतवर्ष का लगभग $\frac{2}{3}$ भाग देशी राज्यों और शेष $\frac{1}{3}$ भाग ब्रिटिश प्रान्तों में बटा हुआ है। कुछ देशी राज्य इतने पुराने हैं कि वे अंग्रेजों के आने के पहले भी मौजूद थे। कुछ राज्य पहले इतने प्रबल थे कि उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बराबरी की सन्धि की। लेकिन देशी राज्यों के आपस की फूट से उनकी बराबरी मातहत या पराधीनता में बदल गई। जब राजा स्वयं पराधीन हो और सब काम रेजिडेण्ट या एजेंट के इशारे से करता हो तो वहाँ प्रजा की पराधीनता दुगुनी बढ़ जाती है। देशी राज्यों के कुछ भोले भाले लोगों को अपनी दुहरी पराधीनता का पता न लगा। वे अपने राजा को स्वतन्त्र समझ कर अपने को भी स्वाधीन मानने लगे। लेकिन ब्रिटिश भारत में एकदम अंग्रेजी शासन हो जाने से लोगों को विदेशी शासन खटकने लगा। पहले १८५७ में लोगों ने विदेशी सत्ता का सशस्त्र मुकाबिला किया। महारानी विक्टोरिया को उदार घोषणा से लोग कुछ समय (१८८५ तक) के लिये बहक गये। इस वर्ष भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरम्भ में कांग्रेस की आवाज़ कमजोर थी। लोकमान्य तिलक के आने से कांग्रेस में जीवन का संचार हुआ। महात्मा गांधी के आने से कांग्रेस सचमुच राष्ट्रीय संस्था बन गई। पूर्ण स्वराज्य इसका ध्येय हुआ। अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन से राष्ट्र अपनी शक्ति समझने लगा। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग का घोर दमन किया और इस अफवाह के फैलाने की कोशिश की कि देश कांग्रेस के साथ नहीं है। इस गलती को अंग्रेजी शासकों के दिमाग से उड़ाने के लिये कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। इसमें कांग्रेस की शानदार विजय हुई। ७ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल द्वारा शासन होने लगा। लेकिन पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिये देश को अभी बहुत कुछ करना है।

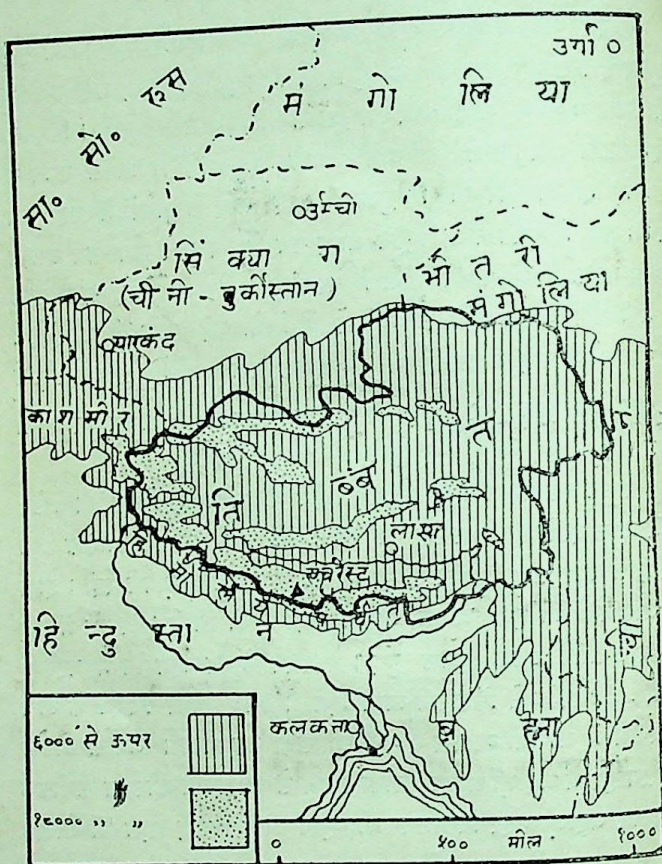
[१०९]



५५-बरमा और स्याम

बरमा और हिन्दुस्तान के बीच में जंगली और पहाड़ी मार्ग कुछ दुर्गम है। समुद्री मार्ग अधिक सुगम है। रंगून का बन्दरगाह कलकत्ते से केवल ७००० मील और मद्रास से १००० मील दूर है। फिर भी हिन्दुस्तान और बरमा का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ब्रिटिश राज्य में शामिल हो जाने पर भी हिन्दुस्तानी तरह तरह के कामों में यहां लग गये। जब हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आन्दोलन ज़ोर पकड़ने लगा तब उसका असर बरमा में भी फैलने लगा। बरमा का मिट्टी का तेल, सागौन की लकड़ी और चावल ब्रिटिश व्यापार के लिये बड़े काम की चीज़ें हैं। भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग रखने के लिये नये शासन विधान के अनुसार १९३५ ई० में बरमा भारतवर्ष से अलग कर लिया गया।

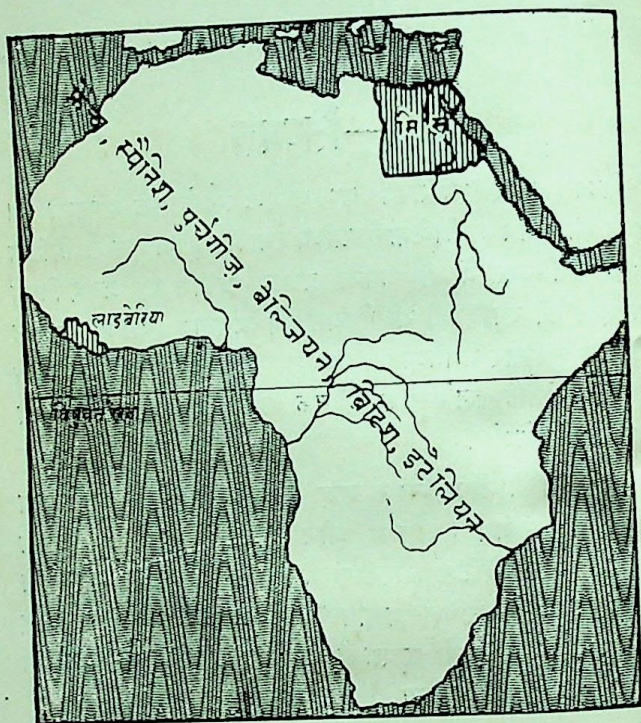
स्याम देश बरमा और फ्रेंच इंडोचीन के बीच में स्थित है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही ने स्याम से लाभ उठाने की भरसक कोशिश की। पर दोनों की पुरानी अनबन से स्याम की स्वाधीनता कायम रही। हाल में जापान ने भी इधर अपना प्रभाव बढ़ाने की सोची। स्याम में कई बार राजनैतिक उथल पुथल हुई। १९३५ के मार्च महीने में यहाँ के राजा प्रजाधिपोक ने सिंहासन त्याग दिया। १९३१ और १९३४ के बीच में स्याम में जापानी व्यापार ५०० फी सदी बढ़ गया। जब से ब्रिटेन ने सिंगापुर में जहाजी अड्डा बनाया है तब से जापान ने क्रास्थल संयोजक में होकर जहाजी नहर निकालने की धुनि की है। यदि इस में जापान को सफलता मिली तो सिंगापुर का महत्व मिट्टी में मिल जायगा। जिस प्रकार पनामा संयुक्त राष्ट्र अमरीका की नहर है उसी प्रकार का नहर जापान के हाथ में होगी।



५६—तिब्बत

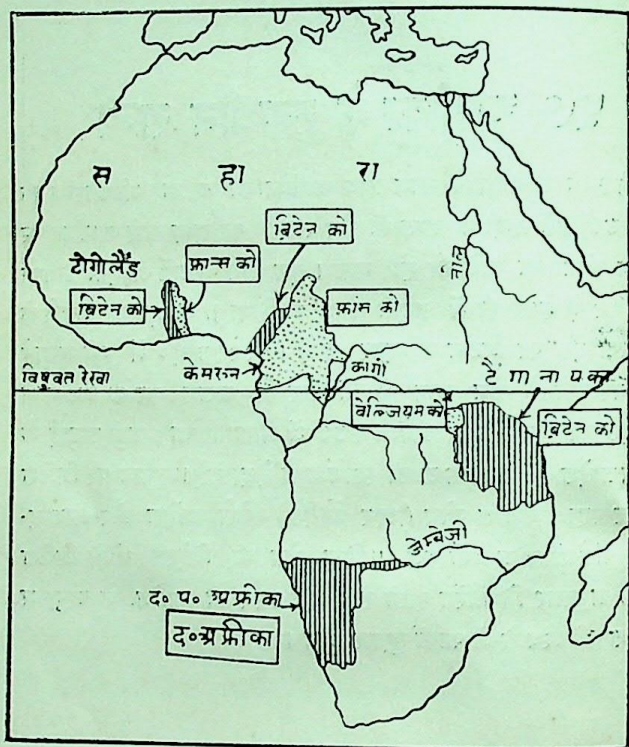
तिब्बत और भारतवर्ष का घनिष्ट भौगोलिक सम्बन्ध है। जब से भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ तब से ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत में भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया। उधर रूस की ज़ारशाही भी तिब्बत को अपने लगी। १९०३-४ में ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत को व्यापारिक द्वार खोलने के लिये मजबूर करने के लिये एक सैनिक टोली लासा (तिब्बत की राजधानी) को भेजी।

१९११ में चीनी क्रांति के बाद तिब्बत में चीनी आधिपत्य फिर मान लिया गया। हाल में चीन में जो गड़बड़ी हुई उससे लाभ उठा कर ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के डलाई लामा से मैत्री करके वहाँ ब्रिटिश प्रभाव फिर स्थापित कर लिया। पर ताशी लामा के लौटने से आशा है कि तिब्बत फिर पूर्ण स्वाधीन हो जावे और वहाँ विदेशियों के हथकंडे न चलने पावें।



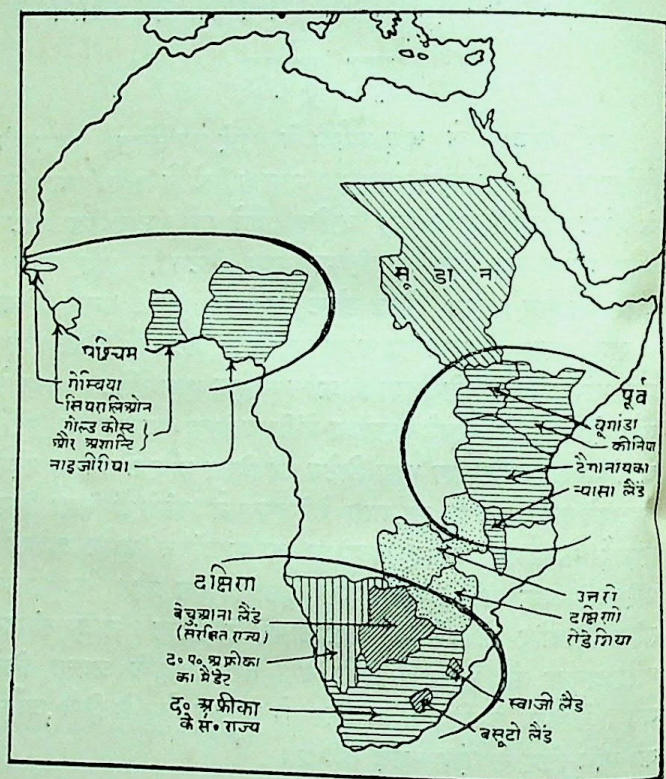
५७--अफ्रीका के स्वाधीन राज्य

योरुपीय अन्वेषण के साथ साथ अफ्रीका का बटना भी आरम्भ हो गया। उन्नीसवीं सदी के अन्त में तीन राज्यों को छ्वाड़ सारे अफ्रीका पर योरुपीय लोगों का अधिकार हो गया। इन तीन भागों में एन्जीसीनिया को १९३५ में हाल ही में इटली ने हड़प लिया। स्वेज़ नहर खुलने के बाद मिस्र देश पर ब्रिटेन की नज़र लगी। १९१४ ई० में बड़ी लड़ाई छिड़ने पर टर्की के नाम मात्र के अधिकार को अलग कर के ब्रिटेन ने मिस्र देश को खुल्लम खुल्ला अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। बड़ी लड़ाई के बाद मिस्र देश को नाम मात्र की स्वाधीनता दे दी गई। सूडान पर ब्रिटिश अधिकार रहा। केनाल जोन (नहर के देश) केरो काहिरा और सिकन्दरिया में अंग्रेज़ी फौज बनी रही। मिस्र देश की विदेशी नीति ब्रिटिश हितों के अनुसार निर्धारित होती रही। १९३६ की सन्धि के अनुसार मिस्र देश की स्थिति में काफी सुधार हुआ।



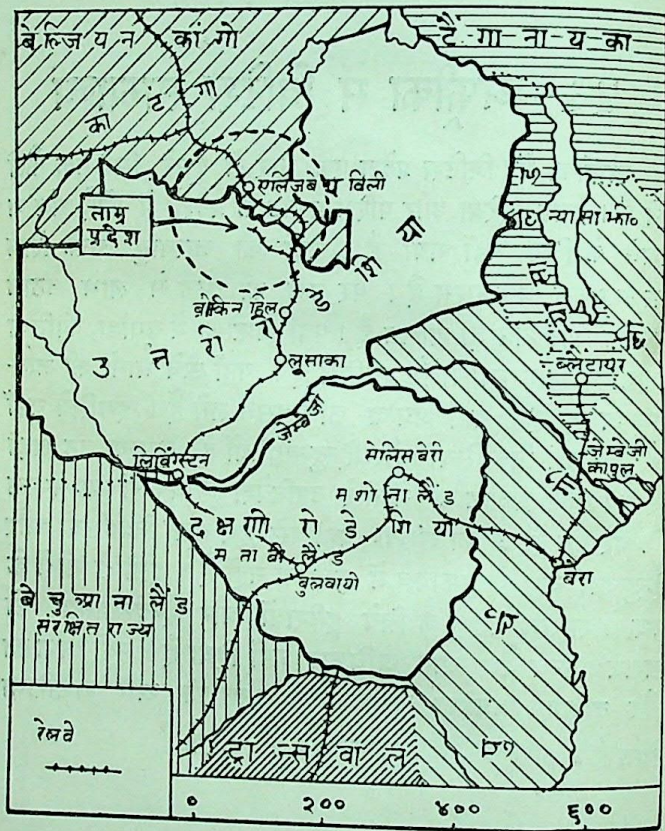
५८—अफ्रीका में जर्मनी के खोये हुए प्रदेश

बड़ी लड़ाई के बाद जर्मनी के सारे उपनिवेशों पर उसके विजेताओं का अधिकार हो गया। नाम के लिये वे लोग (राष्ट्र संघ) के मंडेट (अधिकृत प्रदेश) घोषित किये गये। टोगोलैंड ब्रिटेन और फ्रांस को मिला। पश्चिमी भाग ब्रिटेन के हाथ आया। इसका शासन प्रबन्ध गोल्ड कोस्ट के साथ होता है। नाइजीरिया के पास वाला कैमरून का थोड़ा सा प्रदेश ब्रिटेन को मिला। शेष बड़ा भाग फ्रांस ने ले लिया। फ्रांस ने कुछ भाग मंडेट के नाम से और शेष वैसे ही अपने साम्राज्य में मिला लिया। जर्मन ईस्ट (पूर्वी) अफ्रीका का अधिकांश भाग ब्रिटेन को मिला और टेंगानिका प्रदेश कहलाने लगा। थोड़ा सा भाग बेल्जियम ने कांगो में मिला लिया लड़ाई के समय दक्षिण अफ्रीका की फौजों ने जर्मन दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका को जीता था। इसलिये इस प्रदेश का शासन लोग की ओर से दक्षिण अफ्रीका को ही मिला। नाज़ी संगठन और प्रचार को रोकने के लिये यहाँ तरह तरह के प्रयत्न किये गये। लेकिन उपनिवेशों को फिर से वापिस लेने के लिये जर्मनी की माँग फिर से जोर पकड़ रही है।



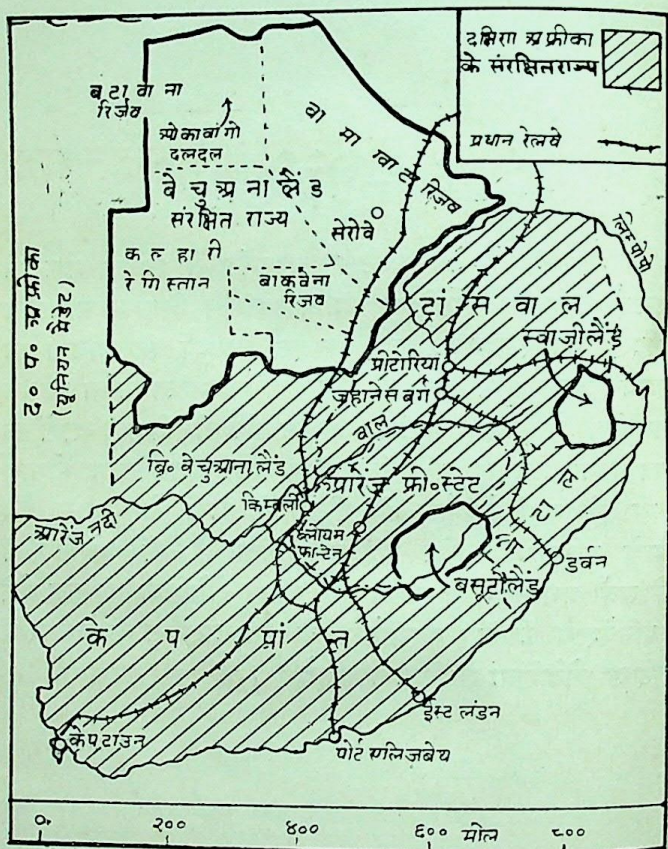
५६—अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य

अफ्रीका में ब्रिटिश प्रदेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले हुये हैं। नाइजीरिया और पश्चिमी तट के प्रदेशों में कोई अंग्रेज बसने के लिये नहीं गया है। यहां की जलवायु उनके लिये अत्यन्त नम और गरम है। पर यहां की उपज से लाभ उठाने के लिये यहाँ अंग्रेजी शासन है। पूर्वी अफ्रीका में यूगांडा, कीनिया टंगानिका और न्यासालैंड शामिल हैं। यहाँ ऊँचे भागों की जलवायु अच्छी है। यहीं अंग्रेज लोग बसने लगे हैं। इसलिये यहाँ बसे हुए मूल निवासियों और हिन्दुस्तानियों की समस्या उठ खड़ी हुई है। दक्षिण-अफ्रीका में गोरे उपनिवेश अधिक संख्या में बसे हैं। पर इन दोनों की संख्या यहाँ बसे हुए मूल निवासियों और हिन्दुस्तानियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसी से गोरों के हाथ में शासन रखने के लिये हथियारों और हिन्दुस्तानियों को शासन प्रबन्ध में समान अधिकार नहीं दिया है। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में भीतर की ओर रोडेशिया स्थित है। उत्तर की ओर सूडान का बड़ा प्रदेश है।



६०—रोडेशिया

१९२३-२४ ई० में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीकन चार्टर्ड कम्पनी से रोडेशिया का अधिकार ले लिया। इसी समय दक्षिणी रोडेशिया को कुछ हद तक स्वराज्य मिल गया। इस समय उत्तरी रोडेशिया का कोई आर्थिक महत्व न था। इसके बाद वहाँ बेल्जियन काटंगा के पास तांबे की विशाल खानों का पता लगा। इससे गोरे पूंजीपतियों को अपार लाभ होगा। साथ ही यहाँ के मूल निवासियों के हितों को खतरा है। इसके दक्षिण की ओर दक्षिण अफ्रीका है जहाँ गोरों के हितों को सर्व प्रधानता दी जाती है। उत्तरी रोडेशिया के कुछ गोरे उपनिवेशक ब्रिटिश पार्ल्यामेन्ट के नियन्त्रण से बचने के लिये दक्षिणी रोडेशिया से मिलाना चाहते हैं।

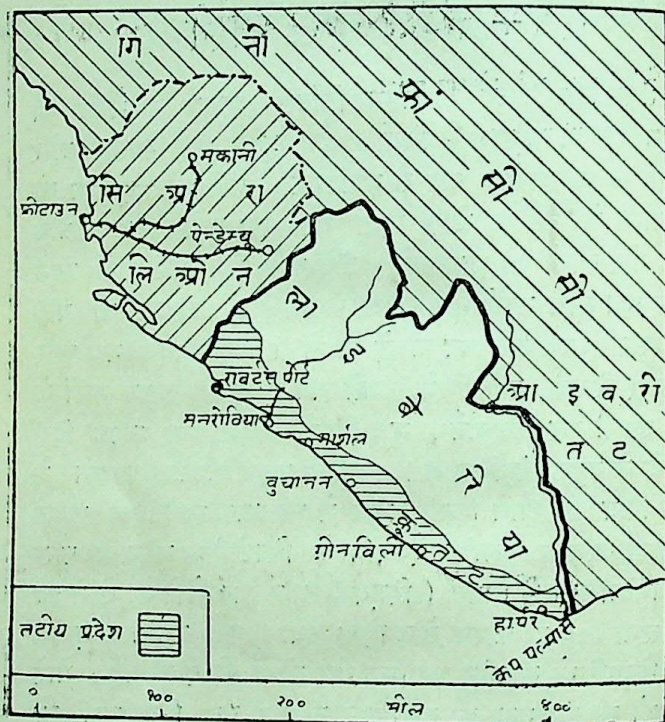


६१—दक्षिणी अफ्रीका के संरक्षित राज्य

१९०९ ई० में जब यूनियन आफ साउथ अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका स्वराज्य) बना तब तीनों ब्रिटिश संरक्षित राज्य ब्रिटिश सरकार के अधिकार में ही बने रहे । यह तीन संरक्षित राज्य थे वेचुआनालैंड (ब्रिटिश वेचुआनालैंड दूसरा है, वह कैपकलोनो का एक भाग है) बसूटोलैंड और स्वाजीलैंड । इन में स्वाजीलैंड सबसे बड़ा है और यूनियन की उत्तरी सीमा पर स्थित है । स्वाजीलैंड और बसूटोलैंड छोटे भाग हैं और यूनियन के ही भीतर स्थित हैं । यूनियन के गोरे लोग इन तीनों प्रदेशों को अपने ही अधिकार में लेना चाहते हैं । लेकिन मूल निवासी सीधे ब्रिटिश शासन को अधिक प्रसन्न करते हैं । ब्रिटिश सरकार ने इन प्रदेशों को एक दम यूनियन को सौंप देने से इनकार किया । लेकिन इन प्रदेशों के आर्थिक विकास को यूनियन सरकार के हाथ में दे दिया ।

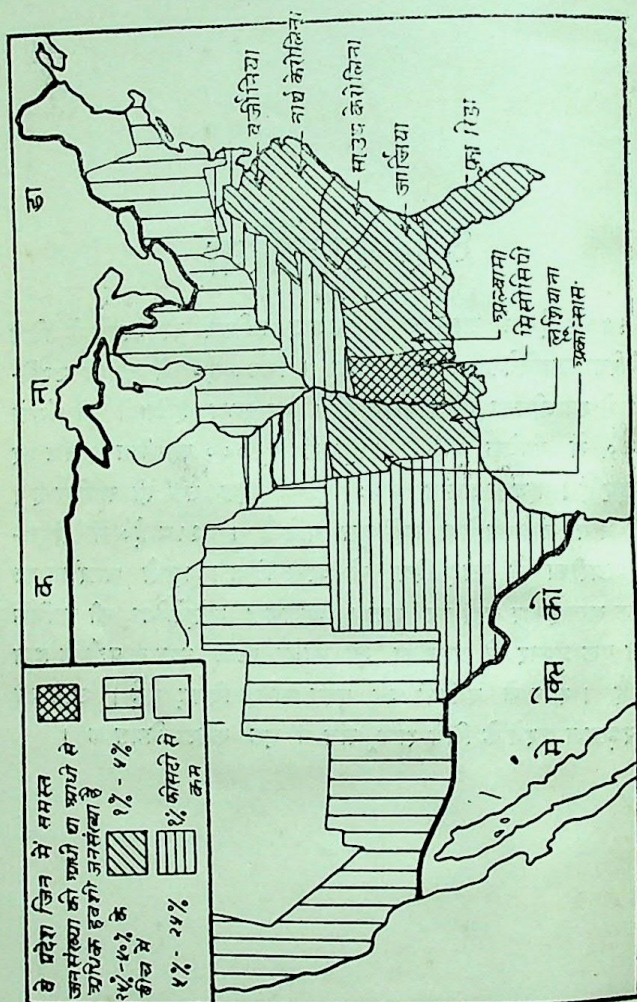
६२—ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका

टैंगानीका टेरीटरी का शासन ब्रिटिश सरकार ने मँडेट की हैसियत से अपने हाथ में लिया। इस प्रदेश का शासन और प्रदेशों से अच्छा है। जब से यूगांडा रेलवे बनी और यूगांडा को मोम्बासा के तट से जोड़ दिया गया तब से कीनिया के ऊँचे भाग गोरे लोगों को भाने लगे। ऊँचे भाग ही कीनिया में रहने योग्य हैं। नीचे भागों में मलेरिया फैलता है। फिर क्या था यहाँ के असली रहने वाले उन अच्छे स्थानों से निकाल दिये गये और नियत (रिजर्व) स्थानों में रखे गये। अच्छे स्थान गोरों के लिये खाली कर दिये गये। मूल निवासियों को जो स्थान दिये गये थे वे बहुत संकुचित थे। इसलिये उनसे ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि आगे किसी हालत में भी उनके स्थानों पर दखल न किया जायगा। लेकिन दैवयोग से विक्टोरिया झील के पास मूल निवासियों के नियत (रिजर्व) स्थान कावीरोंडो में सोने का पता लगा। वादा फौरन तोड़ दिया गया। कई वर्गमील ज़मीन मूल निवासियों से छीन कर फिर गोरे लोगों को दे दी गई। गोरे शासकों की इस तरह की वादाखिलाफी का मूल निवासियों पर गहरा असर पड़ रहा है।



६३—लाइबेरिया

१९१६ ई० में अमरीका के आज़ाद हठियों को बसाने के लिये लाइबेरिया उपनिवेश का आरम्भ हुआ । १८४७ ई० में हबशी उपनिवेशकों ने स्वाधीनता की घोषणा की । पर सभ्य हठियों की संख्या ५०००० से अधिक नहीं है । इन में १२००० अमरीका से लौट कर आये हुए हैं । इनका प्रभाव प्रायः तटीय प्रदेश तक ही सीमित है । भीतरी भागों में वे अधिक नहीं घुस पाये हैं । १९१८ ई० में संयुक्त-राष्ट्र अमरीका ने लाइबेरिया को ऋण दिया । इससे अमरीका का आर्थिक सत्ताहकार यहां आ डटा । आजकल लाइबेरिया की आर्थिक सम्पत्ति एक प्रकार से अमरीका की फायर स्टोन रबर कम्पनी के हाथ रहेन है । रबर के वगीचों की दशा अधिक बिगड़ गई । उसी की जांच पड़ताल करने के लिये राष्ट्र-संघ ने एक कमेटी नियत की ।

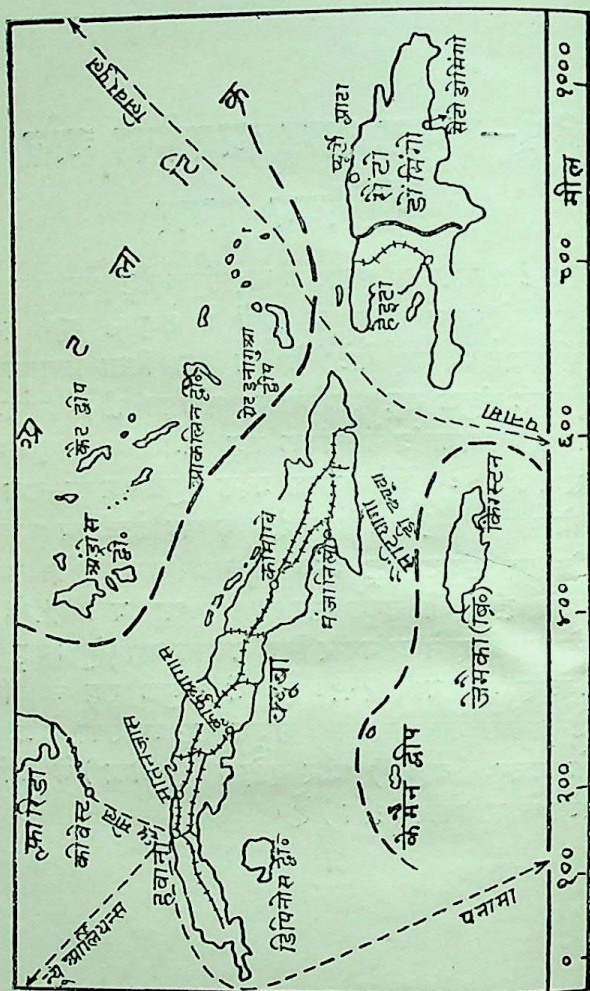


६४—संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हवशियों की समस्या

अब से लगभग चार सौ वर्ष पहले योरुप के गोरे लोग अमरीका में आये। इनकी संख्या तेजी से बढ़ी। लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र अमरीका एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। कुछ गोरे लोग दक्षिणी भाग में खेती के काम में लगे। गरमी में मेहनत से बचने के लिये उन्होंने हजारों हवशी, गुलाम मोल लिये। आज से लगभग ८० वर्ष पहले, गुलामी की प्रथा तो दूर हो गई लेकिन हवशी बने रहे। इस समय संयुक्त राष्ट्र अमरीका की लगभग दस करोड़ आबादी में सवा करोड़ हवशी हैं, जो सारी आबादी के दस फीसदी से अधिक हैं। दक्षिणी रियासतों में हवशी लोग संख्या में गोरी आबादी से कहीं कुछ अधिक कहीं वे उनके बराबर हैं। मिसिसिपी रियासत में वे (हवशी) इस समय भी अधिक (५५ फी सदी) हैं। साउथ कैरोलिया और कुछ दूसरी रियासतों में हवशी लोग पन्द्रह वर्ष पहले अधिक संख्या में थे। आजकल वे घट गये हैं। जहाँ हवशी लोग अधिक संख्या में हैं वहाँ उनके साथ बुरा वर्ताव किया जाता है। वे गोरों के गिरजाघरों, नाटकघरों और भोजनालय में नहीं जा सकते हैं। जो हाल नाजी जर्मनी में यहूदियों का है उससे कम बुरा हाल हवशियों का संयुक्त राष्ट्र अमरीका में नहीं है।

६५—संयुक्त राष्ट्र अमरीका और केरिवियन सागर

१८९८ की स्पेन की लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार केरिवियन सागर के द्वीपों में तेजी से बढ़ने लगी। स्पैनिश लड़ाई के बाद पोर्टोरिको का द्वीप मिला लिया गया। क्यूबा प्रायः संयुक्त राष्ट्र अमरीका का संरक्षित द्वीप बन गया। पनामा के नये प्रजातंत्र में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की देख-भाल होने लगी। १९०३ में केनाल का प्रदेश संयुक्त राष्ट्र को सदा के लिये मिल गया। १९१५ के हस्तक्षेप के बाद हेइटी की आर्थिक सम्पत्ति पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका की निगरानी होने लगी। सैंडोमिंगो द्वीप भी उनके संरक्षण में आ गया। १९१६ में निकारैगुआ में इतने अधिकार मिल गये कि वहाँ संयुक्त राष्ट्र का ही नियंत्रण हो गया। १९१७ ई० में संयुक्त राष्ट्र ने वर्जिन द्वीप डेन्मार्क से मोल ले लिये। संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रभाव-क्षेत्र के उत्तर (बहमा) और दक्षिण (जमैका) में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार (द्वीप) हैं।



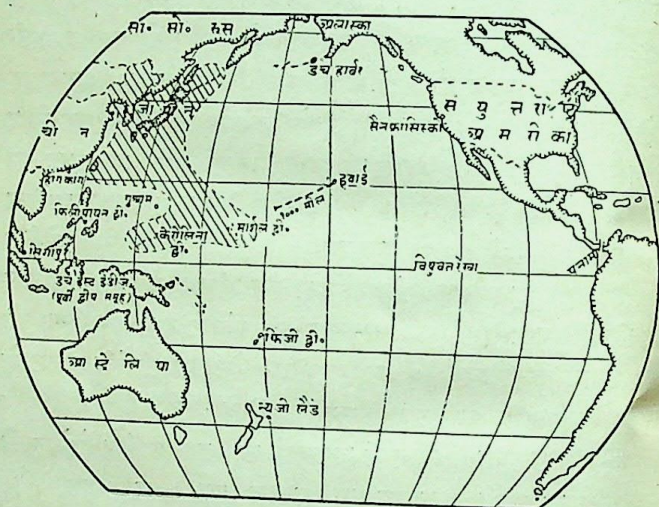
६६-क्यूबा

प्लैट सुधार के अनुसार (जो १९२४ में रद्द कर दिया गया) संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने स्पैनिश अमरीकन लड़ाई के बाद क्यूबा पर अपना संरक्षण घोषित कर दिया। हाल में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रभुत्व के विरुद्ध क्यूबा में राष्ट्रीय विद्रोह उठ खड़ा हुआ, पर क्यूबा की आर्थिक शिकायतें और भी गहरी हैं। क्यूबा की प्रधान सम्पत्ति गन्ने की शक्कर है। लेकिन अमरीकन सरकार अपने यहां की चुकन्दर की शक्कर को प्रोत्साहन देने के लिये क्यूबा के गन्ने की शक्कर को भारी चुंगी लगाकर कम कर रही है। इससे क्यूबा का आर्थिक जीवन ही घोर संकट में पड़ रहा है।

६७—पनामा और निकारेगुआ

स्पैनिश अमरीकन लड़ाई से यह स्पष्ट हो गया कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के लिये या तो दोनों (अटलांटिक और प्रशान्त) महासागरों के तटों पर जहाजी सेना रखे अथवा दोनों तटों को मिलाने के लिये वह एक नहर खोले। अन्त में दोनों महासागरों को जोड़ने के लिये एक नहर की योजना तय की गई। पनामा पहले कोलम्बिया प्रजातन्त्र का अंग था। कोलम्बिया नहर की ज़मीन का दाम बहुत अधिक मांगता था। १९०३ ई० में पनामा ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। दस दिन बाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने इसे स्वीकार कर लिया। पनामा की नई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका को नहर बनाने के लिये ० मील चौड़ी पेट्री अटलांटिक तट से प्रशान्त महासागर के तट तक सदा के लिये दे दी।

१९१६ से पनामा नहर में जहाजों की इतनी भीड़ होने लगी कि दूसरी नहर की आवश्यकता प्रतीत हुई। नहर-मार्ग और दोनों तटों पर जहाजी अड्डा बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने निकारेगुआ से सन्धि कर ली। लेकिन निकारेगुआ की नहर बनाने में ७० करोड़ डालर खर्च होंगे। पनामा नहर में नया झाल १४ करोड़ रुपये में ही बन जायगा। इसलिये निकारेगुआ की नहर बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।



६८—प्रशान्त महासागर में जातियों का संघर्ष

१८९८ ई० में संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने हवाई द्वीप को (जो प्रशान्त महासागर के लम्बे जल-मार्ग में अध्विच स्थित है) मिला लिया । फिर उसने कुछ महीनों के बाद फिलीपाइन द्वीप और गुआम द्वीप ले लिये । इससे संयुक्त राष्ट्र अमरीका प्रशान्त महासागर की एक शक्ति बन गई । बड़ी लड़ाई के बाद प्रशान्त महासागर के जो द्वीप विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित थे वे लीग की ओर से जापान को मिल गये । इससे जापानी अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उस जलमार्ग को काटने लगा जो पनामा नहर और फिलीपाइन द्वीपों के बीच में स्थित है । जहाज़ी सैनिकों का अनुमान है कि हवाई द्वीप से १००० मील से अधिक आगे संयुक्त राष्ट्र अमरीका बलपूर्वक नहीं बढ़ सकता है । संयुक्त राष्ट्र से अमरीका नाम-मात्र को फिलीपाइन द्वीप का स्वाधीनता भले ही मिल जाय, लेकिन १९४५-४६ ई० के पहले अमरीका अपना नियन्त्रण ढीला नहीं कर सकता । अगर अमरीका फिलीपाइन द्वीप का पूरी स्वाधीनता दे दे, तो उसे जापान के हाथ में चले जाने का डर है । जापान की बढ़ती हुई शक्ति से ब्रिटिश साम्राज्य के हांगकांग और सिंगापुर को भी डर है । इसी तरह डच लोगों के पूर्वी द्वीप समूह का तेल भी जापान के बड़े काम का है ।

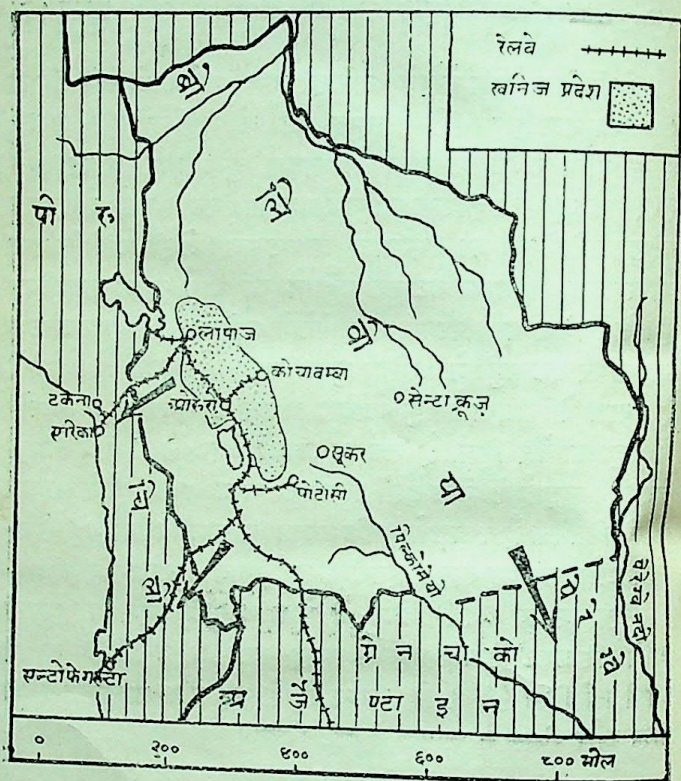
६६—दक्षिणी अमरीका में संयुक्त राष्ट्र अमरीका का साम्राज्यवाद

संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने जब से केरिबियन सागर की ओर बढ़ना शुरू किया है तब से दक्षिणी अमरीका की रियासतें सन्देह की दृष्टि से देख रही हैं। पनामा नहर ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के पूर्वी कारबारी प्रदेश को प्रशान्त महासागर के प्रजातन्त्र राष्ट्रों को सैकड़ों मील नज़दीक कर दिया है। मनरो डाक्ट्रिन (सिद्धान्त) के अनुसार पहले संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने योरुप के राज्यों को दक्षिणी अमरीका में हस्तक्षेप करने से रोक दिया था। हाल में इस डाक्ट्रिन के अनुसार दक्षिणी अमरीका की खटपट में हस्तक्षेप करने का एक मात्र अधिकार अपने ही ऊपर ले लिया है। दक्षिणी अमरीका में संयुक्त राष्ट्र की सब से कड़ी आर्थिक लड़ाई ब्रिटेन के साथ है। अर्जेंटाइना में यह आर्थिक लड़ाई और भी अधिक विकट है। यहां सब से अधिक व्यापारिक उन्नति हुई है। १९३३ की सन्धि से अर्जेंटाइना ने ब्रिटेन को कई व्यापारिक सुविधायें कर दी हैं। लेकिन समस्त दक्षिणी अमरीका में १९१३ से १९२७ तक ब्रिटेन का निर्यात (ब्रिटेन से यहाँ आने वाला माल) २५ फ़ीसदी से घटकर १६ फ़ी सदी रह गया। इसी बीच में संयुक्त राष्ट्र अमरीका का निर्यात यहां २४ फ़ी सदी से बढ़ कर ३८ फ़ी सदी हो गया।

७०—बोलिविया और पेरुग्वे की लड़ाई

बोलिविया और पेरुग्वे दक्षिणी अमरीका के दो ऐसे भीतरी प्रजातन्त्र राष्ट्र हैं जो किसी समुद्र तट को नहीं छूते हैं। १९३२ में इन दोनों राष्ट्रों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। इसका अन्त १९३५ के जून की क्षणिक सन्धि से हुआ। यह लड़ाई ब्रेनचाको प्रदेश के लिये हुई थी। एण्डीज को उच्च पर्वत श्रेणी ने बोलिविया को प्रशान्त महासागर तट तक पहुँचने का मार्ग दुर्गम बना दिया है। बोलिविया वाले परना और पेरुग्वे नदियों द्वारा अटलांटिक महासागर तक पहुँचने के लिये सुगम जलमार्ग चाहते हैं। पेरुग्वे देश वाले बोलिविया का कुछ प्रदेश चाहते हैं। जब से ब्रेनचाको में मिट्टी का तेल मिला है तब से दोनों देशवाले इसको चाहने लगे हैं। लड़ाई में जिन देशों के गोला बारूद और दूसरे सामान की विक्री होती है वे चाहते थे कि उनका सामान बिकता रहे। इसलिये और भी यह लड़ाई इतने अधिक समय तक जारी रही।

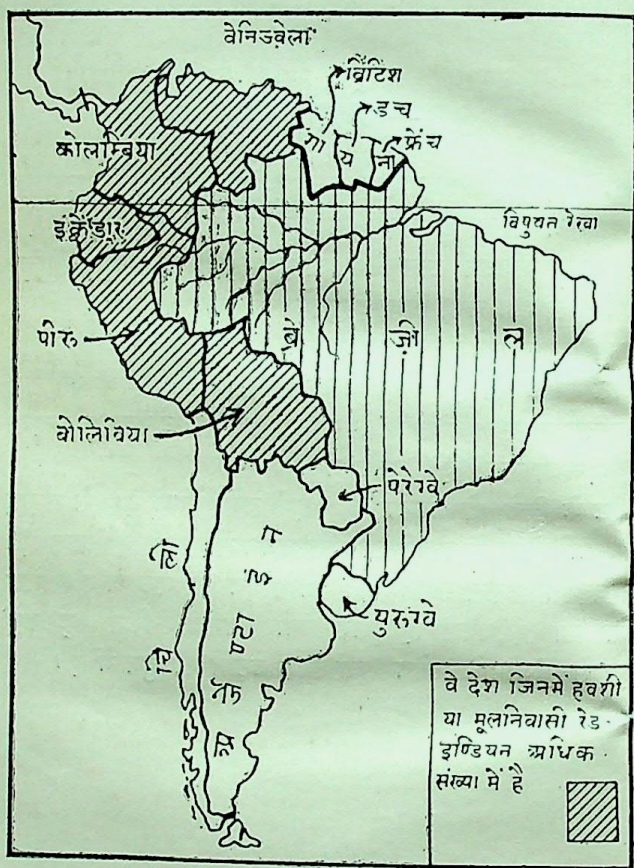
एक समय बोलिविया ने टेकनाएरिका प्रदेश पर अपना अधिकार प्रगट किया। इससे समुद्र तट तक उसकी पहुँच हो जाती। लेकिन १९२९ के समझौते से यह टेक नाएरिका प्रदेश पीरू और चिली ने आपस में बांट लिया।



[१४२]

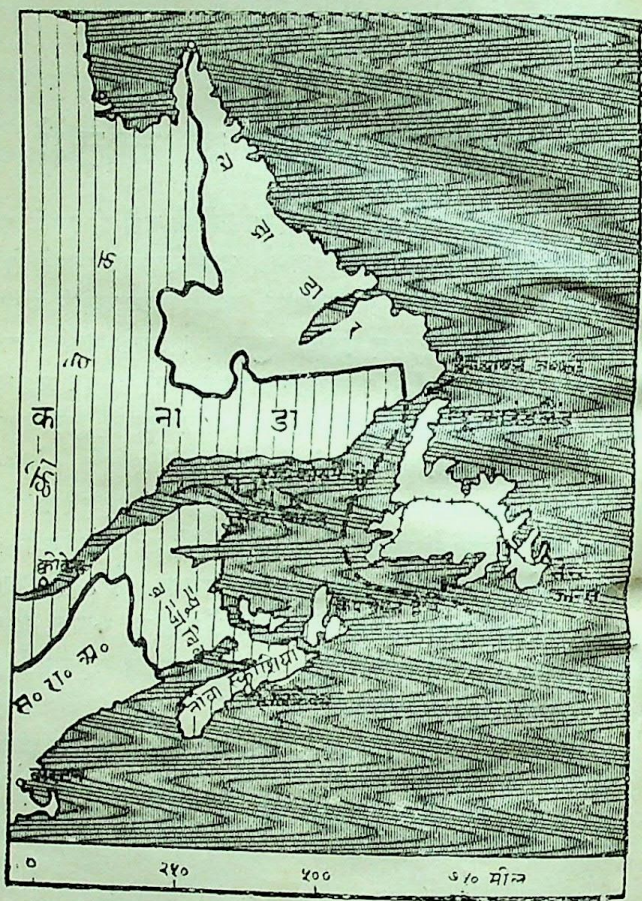
७१—बोलिविया

खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से नई दुनिया में संयुक्त राष्ट्र अमरीका और मेक्सिको के बाद तीसरा नम्बर बोलिविया का ही है। दुनिया भर में जितनी टीन निकलती है उसकी एक चौथाई बोलिविया में होती है। चीन के बाद सुरमे की उत्पत्ति के लिये संसार में दूसरा स्थान बोलिविया का ही है। यहां चाँदी और सीसा भी काफी निकलता है। बाहर भेजने के लिये बोलिविया की यह सब खनिज सम्पत्ति चिली के एरिका और एरटोफेगस्टा बन्दरगाहों को भेजी जाती है। दूसरा मार्ग पेरूग्वे नदी के द्वारा अटलांटिक तट के लिये हो सकता है। इसीलिये पेरूग्वे देश से लड़ाई छिड़ी। बोलिविया में मूलनिवासी इण्डियन लोगों की अधिकता है। उनकी बड़ी विकराल गरीबी है। बोलिविया में एक ओर खनिज सम्पत्ति की अधिकता है दूसरी ओर गरीब लेकिन हट्टे कट्टे मजदूरों से पूंजीपति लोग पूरा लाभ उठाने की धुन में हैं।



७२-दक्षिणी अमरीका की जातियाँ

गायना में योरुपीय पूँजीपति और शासकों ने वहाँ की आर्थिक सम्पत्ति से लाभ उठाने के लिये अपने उपनिवेश बहुत पहले से बनाये हैं। यहाँ मूलनिवासियों के साथ चीनी, हिन्दुस्तानी और हवशी लोग भी काफी तादाद में पहुँच चुके हैं। इनके अतिरिक्त कोलम्बिया, यूक्वेडार, पीरू और बोलिविया के चार खनिज प्रधान प्रजातन्त्र राष्ट्रों में भी मूलनिवासियों की अधिकता है। वे बहुत सस्ती मजदूरी पर काम करने के लिये तयार हो जाते हैं। वेनिज्वेला और गायना में हवशी और मुलाटो वर्णसंकर लोगों की अधिकता है। ब्रेज़िल में मुलाटो के अतिरिक्त गोरे और मूलनिवासी इण्डियन लोगों की जन-संख्या प्रायः बराबर है। शीतोष्ण प्रदेश के चार प्रजातन्त्र राष्ट्रों (चिली, अर्जेण्टाईना, यूरुग्वे और पैराग्वे) में मूलनिवासी घटते घटते अल्पसंख्या में रह गये हैं। गोरो की प्रधानता हो गई है।



न्यूप
ई०
सीम
रहते
प्रधा
सरव
पन
म
लेड
ब्रि
दिय

७३-न्यूफाउंडलैंड

न्यूफाउंडलैंड का शासन प्रबन्ध कनाडा से अलग है । न्यूफाउंड से ही पड़ोस का लब्राडोर प्रदेश मिला हुआ है । १९२७ ई० में प्रिवी काउंसिल ने कनाडा के बचीबेक प्रान्त और लब्राडोर की सीमा निर्धारित की थी । लब्राडोर में केवल ४२६४ मनुष्य रहते हैं । न्यूफाउंडलैंड की जनसंख्या लगभग २ लाख है । प्रधान सम्पत्ति मछली और लकड़ी है, लेकिन यहाँ की सरकार घाटे से चलती थी । न्यूफाउंडलैंड के दिवालिये-पन की जाँच करने के लिये १९३३ के नवम्बर मास में एक रायल कमिशन बैठा । इस कमिशन ने सिफारिश की है कि न्यूफाउंडलैंड से प्रतिनिधि संस्थाएँ उठा ली जावें और इसका शासन-भार ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक कमिशन को सौंप दिया जावे ।

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी



इतिहास-चित्रावली

इतिहास-चित्रावली—पृष्ठ-संख्या १४०, मूल्य १२ आने । इसके पहले भाग में भारतवर्ष के समय-समय पर बदलते हुए ५० राजनैतिक नक्शे और उनकी व्याख्या, प्रसिद्ध लड़ाइयों के खाके और भारतवर्ष की प्रमुख घटनाओं की सनवार सूची है । दूसरे भाग में भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न समयों पर कैसा जीवन रहा है, उसके चुने हुये चित्र दिये हुये हैं । कुछ ऐसे दुर्लभ चित्र हैं जिन्हें आप पहली बार इसी चित्रावली में देखेंगे ।

मैनेजर—“भूगोल”, इलाहाबाद

JULY, 1938

REGD. NO. A

DIGITIZED C-DAC
2005 2006
08 JUL 2006

*Published by the Editor (Pt. Ram Narain
B. A.) and printed by Sheopal at the
Press, 306, Jamuna Road, Allahabad*

CO. A

rai
e 1
abi

PAYMENT PROCESSED
Vide Bill No 79 Dated 22.3.13
Anis Book Binder

